● वर्ष-2
● अंक-168
रायपुर, शुक्रवार
03 मार्च 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmailÐcom

इन दिनों

समीर चौगांवकर

भाजपा की छोटी जीत का बड़ा संदेश

पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनाव के परिणाम लगभग साफ़ हो गए हैं। चुनाव परिणाम वैसे ही आए हैं जैसी उम्मीद थी। त्रिपुरा और नगालैंड में भाजपा की वापसी तय हो गई है। मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। त्रिपुरा में शाही वंशज प्रद्योत देवबर्मा के नेतृत्व में टिपरा मोथा ने बेहतर प्रदर्शन किया है। टिपरा मोथा 13 सीटें जीतने में सफल रही। टिपरा मोथा ने त्रिपुरा में भाजपा के सहयोगी दल को भारी नुकसान पहुंचाया लेकिन भाजपा को सत्ता में आने से नहीं रोक पाई। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी सीटों पर जीत गए है। त्रिपुरा में माणिक साहा ने पश्चिम त्रिपुरा की नगर बरदोवाली, मेघालय में कॉनराड संगमा ने वेस्ट गारो हिल्स की दक्षिण तुरा (एसटी) सीट से और नगालैंड में नेफ्यू रियो को कोहिमा की नॉर्दन अंगामी एसटी सीट पर जीत मिली। इस चुनाव की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नागालैंड में पहली बार कोई महिला चुनाव जीती है। हेकानी जाखालू दीमापुर सीट जीतकर नगालैंड की पहली महिला विधायक बन गई हैं। 1963 में नगालैंड राज्य बना, तब से अब तक कोई महिला विधानसभा चुनाव नहीं जीती थी। नार्थ ईस्ट के राज्यों में मोदी और शाह के उदय के बाद भाजपा ने जिस तरह से पसीना बहाया है वह बताता है कि मोदी और शाह के लिए कोई भी राज्य छोटा नहीं है। मोदी और शाह जैसे रणनीतिकार छोटे राज्यों से भी बड़ा फायदा निकालने में माहिर है। यही कारण है कि हर चुनाव को जीवन मरण का प्रश्न मानने वाली भाजपा ने इन तीनों राज्यों में पूरी पार्टी उतार कर ताकत से चुनाव लड़ा। भाजपा यह संदेश देना चाहती थी कि वह सिर्फ हिंदीभाषी राज्यों की पार्टी नहीं है। देशभर में उसके कार्यकर्ता हैं। लंबे समय से जिन राज्यों में वामदलों और कांग्रेस की सरकार थी, वहां अपनी लगातार दूसरी बार सरकार बनाना इसी बात की ओर इशारा करता है। भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि विपक्ष उसे सिर्फ हिंदू बाहुल्य वाले क्षेत्र की पार्टी समझने की भूल न करें। क्रिश्चियन बाहुल्य नार्थ ईस्ट के इन राज्यों में भाजपा की जीत का यही संकेत है। फरवरी महीने में ही प्रधानमंत्री ने तीन बार इन राज्यों का दौरा किया था। गृहमंत्री अमित शाह, और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता लगातार यहां जाते रहे हैं। प्रधानमंत्री 2017 के बाद से 47 बार नार्थ-ईस्ट जा चुके हैं। चुनाव से पहले उन्होंने त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय में 3 बड़ी रैलियां कीं। नार्थ-ईस्ट के 8 राज्यों में हर 15 दिन में कोई न कोई केंद्रीय मंत्री जरूर पहुंचता है।

पूर्वोत्तर में लहराया एक बार फिर भगवा

त्रिपुरा-नगालैंड में बीजेपी गठबंधन की बनेगी सरकार

नईदिल्ली। त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। त्रिपुरा और नगालैंड में भाजपा गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि मेघालय में भाजपा की पुरानी सहयोगी एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यहां भी भाजपा सरकार का हिस्सा बन सकती है।

2018 में यहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे बिप्लब कुमार देब को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि, अभी हाल ही में चुनाव से कुछ महीनो पहले बिप्लब कुमार देब की जगह माणिक साहा को राज्य सरकार की कमान सौंप दी गई। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई बार साफ कर दिया कि माणिक साहा ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि, उपमुख्यमंत्री जिश्नु देब वर्मा जरूर चुनाव हार गए हैं। ऐसे में उनकी जगह अब प्रतिमा भौमिक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। प्रतिमा केंद्रीय मंत्री हैं और उन्हें भाजपा ने धानपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया था। प्रतिमा ने करीब 3500 वोटों से चुनाव में जीत हासिल की है। चर्चा ये भी थी कि प्रतिमा भौमिक को मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। हालांकि, अभी इसकी संभावना कम ही दिखती है। टिपरा मोथा भी सरकार का हिस्सा हो सकती है।

टिपरा मोथा के मुखिया प्रद्योत देबबर्मा ने भाजपा को समर्थन देने का एलान भी कर दिया है।

नगालैंड में नेफ्यू रियो को फिर मिलेगा ताज

इस बार नगालैंड की 59 सीटों पर चुनाव हुए। यहां जुन्हेबोटो की आकुलुटो सीट से भाजपा प्रत्याशी और निर्वतमान विधायक काजहेटो किन्मी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर चुनाव नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) का गठबंधन हुआ है। इसके तहत एनडीपीपी ने 40 और भाजपा ने 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इसके अलावा कांग्रेस और एनपीएफ अलग-अलग चुनाव लड़े। कांग्रेस ने 23 और एनपीएफ ने 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 19 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव में ताल ठोकी थी।

2018 में यहां विधानसभा के सभी 60 सदस्य सरकार का हिस्सा बन गए थे। मतलब कोई भी विपक्ष में नहीं था। एनडीपीपी के नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इस बार भी भाजपा और एनडीपीपी गठबंधन सीधे तौर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस और एनपीएफ को बड़ा झटका लगा है। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव में कुछ खास हासिल नहीं किया। अब मुख्यमंत्री की बात करें तो यहां एनडीपीपी के मुखिया नेफ्यू रियो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। रियो को भाजपा का समर्थन भी है। इस चुनाव में जेडीयू के चार, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के एक उम्मीदवार ने भी जीत हासिल की है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का विधायक भी सरकार में शामिल हो सकता है।

मेघालय में कोनराड सीएम

मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एनपीपी को 25 सीटों पर जीत मिली है। वहीं, यूडीपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। यूडीपी ने 11 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा को तीन सीटों पर जीत मिली है। एचएसपीडीपी और पीडीपी के दो-दो उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। सभी 2018 से एनपीपी के साथ सरकार में शामिल थे। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से इन पार्टियों के सहारे एनपीपी के मुखिया कोनराड संगमा मुख्यमंत्री बन जाएं।

डबल इंजन सरकार राज्य की प्रगति के लिए काम करती रहेगी: मोदी

भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने नागालैंड में 37 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य की तरक्की के लिए काम करती रहेगी। मैं नागालैंड के लोगों को राज्य की सेवा करने के लिए एक और जनादेश के साथ गठबंधन को आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद देता हूं। डबल इंजन की सरकार प्रदेश की तरक्की के लिए काम करती रहेगी। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के लिए उनकी सराहना करता हूं, जिन्होंने यह परिणाम सुनिश्चित किया। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है, भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगी ने राज्य में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार शाम 6 बजकर 10 मिनट पर साझा किए गए ताजा रुझानों के मुताबिक, बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है।

टारगेट किलिंग के आरोप पर भारी हंगामा

- जल जीवन मिशन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस, वाकआउट

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामा के साथ शुरू हुआ। सदन में जल जीवन मिशन का मुद्दा उठा। बीजेपी विधायक रजनीश सिंह ने बिलासपुर संभाग में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों और भुगतान का मामला उठाया। सवाल पर मंत्री गुरु रुद्र कुमार के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन में जमकर किया हंगामा। इसके बाद असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन का वाकआउट किया। रजनीश सिंह ने मामले में जांच और शिकायतों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री गुरू रुद्र कुमार ने कहा कि जांच हुई है और अधिकारी पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। विपक्ष के विधायक शिवरतन शर्मा ने दोषी अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए एफआईआर की मांग की। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष कौशिक के बयान के बाद बिफरे सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया।

कार्यवाही तीन बार स्थगित

शून्यकाल में, बस्तर में भाजपा नेताओं की हत्या का मामला उठने पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर नोंकझोंक हुई। आरोप प्रत्यारोप के दौरान भारी हंगामे की वजह से तीन बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई।शून्यकाल शुरू होते ही भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने बस्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला उठाते हुए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि बस्तर में भाजपा के चार नेताओं की टारगेट किलिंग हुई है। आदिवासी मारा जा रहा है। धर्मांतरण हो रहा है। उसे संरक्षण दिया जा रहा है। इस मामले में चर्चा में शामिल होते हुए भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है।

भाजपा नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। बस्तर में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। प्रतिपक्ष के आरोपों का सत्ता पक्ष ने विरोध किया। इस पर दोनों पक्षों के बीच जमकर नोंकझोंक हुई। सत्ता पक्ष ने कहा कि पूरे देश में अघोषित आपातकाल लगा है। इस पर हंगामा हुआ।

आसंदी पर विराजमान उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने दस मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने इस मुद्दे पर सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि आपके लोगों की भी हत्या हुई है, जरा शर्म करो। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिर टकराव हुआ। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि भाजपा के राज में हमारे नेताओं को चुन चुन कर मारा गया।

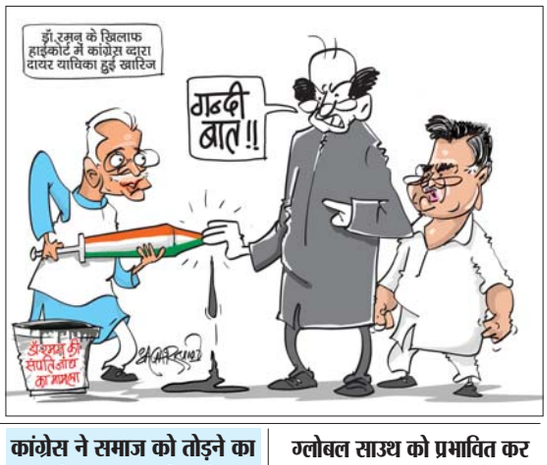

प्रमुख समाचार

भाजपा विधायक की टिप्पणी से भड़के राकांपा विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया

मुंबई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम सतपुते द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार के बारे में की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए राकांपा के विधायकों ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राकांपा सदस्यों द्वारा सतपुते से उनकी टिप्पणी के लिए माफी मांगने पर जोर दिये जाने के बीच पीठासीन अधिकारी योगेश सागर ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तो विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि वह रिकॉर्ड देखेंगे और टिप्पणी को हटा देंगे, हालांकि राकांपा विधायक माफी की मांग पर अड़े रहे। इस बीच, भाजपा विधायक आशीष शेलार ने राकांपा सदस्यों को बताया कि राकांपा नेता जितेंद्र आव्हाड ने 'सनातन धर्म' के बारे में कथित रूप से नकारात्मक टिप्पणी की थी। हालांकि, राकांपा ने इसे खारिज कर दिया।

विशेष अदालतों के मौजूदा कामकाज से बहुत संतुष्ट नहीं-रीजीजू

नयी दिल्ली। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रीजीजू ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के मौजूदा कामकाज से बहुत संतुष्ट नहीं है। उन्होंने इस तरह की अदालतों की क्षमता बढ़ाने के लिए जांच एजेंसियों और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को मजबूत करने की वकालत की। रीजीजू ने यहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में अपने संबोधन में किसी व्यक्ति या राज्य का नाम लिये बिना कहा कि कुछ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और अधिक काम करना होगा। फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (एफटीएससी) योजना को न्याय विभाग के अधीन संचालित किया जा रहा है। कानून मंत्री ने कहा, ''मुझे सुनिश्चित करना है कि जो भी विधायी काम किये जाने हैं, जमीन पर किये जाएं।''

खुफिया एजेंसियों ने खालिस्तान सरगना पर हमले की जताई आशंका

चंडीगढ़। खुफिया एजेंसियों ने खालिस्तानी नेता और वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह पर हमले की साजिश रचने की चेतावनी दी है। अलर्ट में कहा गया है कि यह हमला देश विरोधी तत्वों द्वारा रचा जा रहा है और यह कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश है। इसकी जानकारी पंजाब पुलिस को दे दी गई है और खुफिया एजेंसियों ने पुलिस से वारिस पंजाब डे के जिलाध्यक्षों को मिलने वाले फंड पर नजर रखने को कहा है। सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि अमृतपाल सिंह को सोशल मीडिया पर भिंडरावाले 2.0 के रूप में प्रचारित करने के लिए पाकिस्तान की इंटर-सर्विस इंटेलिजेंस (ड्डस्ड्ड) से फॉडिंग मिल रही है। जरनैल सिंह भिंडरावाले अलग सिख राष्ट्र खालिस्तान के समर्थक थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लूस्टार के दौरान सेना ने उन्हें मार गिराया था। यह उनके सहयोगी लवप्रीत सिंह तूफान की गिरफ्तारी को लेकर अजनाला में अमृतपाल सिंह के समर्थकों और पंजाब पुलिस के बीच झड़प के कुछ दिनों बाद आया है।

कांग्रेस ने समाज को तोड़ने का किया काम,-बोम्मई

बेंग्लूरू। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि हमे लोगों से सकारात्मक उत्तर मिल रहा है। हमे 100त्न वकीन है कि इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत में आ जाएगी। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा हैं क्योंकि उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया है। भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा के योगदान की सराहना करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कर्नाटक के लोगों से आगामी विधानसभा चुनावों में कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के सपने को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय मेत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कर्नाटक की जनता यह मानती है कि सबसे विश्वसनीय पार्टी भाजपा है। हिंदुस्तान की जितनी भी बाकी की राजनीतिक पार्टियां है सिर्फ कहने वाली पार्टी है, भाजपा करने वाली पार्टी है और लोगों से अपील है कि भाजपा को ही अपना समर्थन दें।

ग्लोबल साउथ को प्रभावित कर रहा यूक्रेन का मुद्दा, चीन को लेकर कही यह बातः एस जयशंकर

नई दिल्ली। भारत जी-20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। जी-20 के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में दो दिवसीय बैठक चल रही है। इन सबके बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी बात कही है। एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन का मुद्दा ग्लोबल साउथ को प्रभावित कर रहा है। हमारा प्रयास है कि 'ग्लोबल साउथ' की आवाज सुनी जाए। उन्होंने कहा कि जी-20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में अध्यक्षता सारांश और परिणाम दस्तावेज स्वीकार किये गये। उन्होंने कहा कि जी-20 का परिणाम दस्तावेज प्रमुख चुनौतियों से निपटने के जी-20 के संकल्प को प्रदर्शित करता है। बैठक में अनेक मुद्दों पर सहमति बनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जी-20 के संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं कर पाने के संबंध में कहा कि दो पैराग्राफ पर सहमति नहीं बन सकी। जी-20 की बैठक में संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं होने के संबंध में जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष से जुड़े मुद्दे भी रहे। यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत के संबंध में जयशंकर ने कहा कि अलग-अलग धारणाएं सामने आई।

त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड चुनाव में क्यों फेल हुई कांग्रेस?

हिमांशु मिश्रा

पूर्वोत्तर के तीन राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने नगालैंड और त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। मतलब दोनों राज्यों में भाजपा सरकार बनना तय है। मेघालय में पेंच जरूर फंसा है, लेकिन यहां भी पिछली बार के मुकाबले भाजपा ने बढ़त हासिल की है। यहां एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 2018 में एनपीपी ने भाजपा और यूडीपी के साथ मिलकर ही सरकार बनाई थी। ऐसे में पूरी संभावना है कि इस बार भी सरकार बनाने के लिए ये तीनों दल एकसाथ आ जाएं। खैर, तीनों राज्यों के चुनावी नतीजों ने सबसे ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। त्रिपुरा में लेफ्ट से गठबंधन करने के बाद कांग्रेस को जरूर दो सीटों की बढ़त मिली है, लेकिन यहां भी सरकार से दूर ही रहना पड़ेगा। नगालैंड में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं, मेघालय में 21 से पांच सीटों पर कांग्रेस आकर सिमट गई। मतलब यहां कांग्रेस को 16 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। 2018 में कांग्रेस ने यहां 21 सीटों जीतीं थीं, हालांकि बाद में इनके ज्यादातर विधायक टूटकर टीएमसी में चले गए थे। तीनों चुनाव के नतीजों से साफ होता है कि कांग्रेस पूर्वोत्तर में बुरी तरह से फेल हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक समय जहां कांग्रेस का राज हुआ करता था, वहां अब इतनी बुरी स्थिति कैसे हो गई?

यहां भारतीय जनता पार्टी ने आईपीएफटी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ गठबंधन कर लिया था। चुनाव के नतीजों में भाजपा ने सूबे में अपनी सत्ता बरकरार रखी। भाजपा को 30 सीटों पर जीत मिल चुकी है और दो पर बढ़त बनी हुई है। भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली आईपीएफटी ने एक सीट पर जीत हासिल की है। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस ने तीन सीटों पर जीत हासिल की, जबकि लेफ्ट के खाते में 11 सीटें आईं।

इस बार नगालैंड की 59 सीटों पर चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) का गठबंधन हुआ। इसके अलावा कांग्रेस और एनपीएफ अलग-अलग चुनाव लड़े। 19 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव में ताल ठोकी थी। 2018 में यहां विधानसभा के सभी 60 सदस्य सरकार का हिस्सा बन गए थे। मतलब कोई भी विपक्ष में नहीं था। इस बार भी यहां भाजपा गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की। भाजपा के 20 में से 13 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। वहीं, एनडीपीपी के 40 में से 25 प्रत्याशी विजयी हुए। कांग्रेस यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई।

सबसे रोमांचक मुकाबला मेघालय में हुआ। 59 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों ने आज सभी को हैरान कर दिया। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इनके 25 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर यूडीपी रही। भाजपा के तीन, टीएमसी के पांच, कांग्रेस के पांच, एचएसपीडीपी, पीडीएफ के दो-दो उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। दो निर्दलीय विधायक भी चुने गए। वाइस ऑफ द पीपल पार्टी के चार उम्मीदवार चुनाव जीत गए।

कांग्रेस क्यों फेल हुई?

इसे समझने के लिए हमने पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजय मिश्र से बात की। उन्होंने कांग्रेस के फेल होने के कुछ कारण बताए। पूर्वोत्तर के इन तीन राज्यों में कांग्रेस ने कोई मेहनत नहीं की। राहुल गांधी ने केवल मेघालय में एक चुनावी रैली की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी कम ही नजर आए। राहुल, खरगे समेत सभी बड़े नेताओं के इससे दूर रहने की बड़ी वजह यह हो सकती है, जबकि इनके मुकाबले भाजपा कहीं ज्यादा सक्रिय दिखी। जिन तीन राज्यों में चुनाव हुए, उनमें से दो में पिछली बार कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। ये राज्य त्रिपुरा और नगालैंड हैं। यही कारण है कि त्रिपुरा में कांग्रेस ने खुद से कहीं ज्यादा सीटें लेफ्ट को दे दी। गठबंधन का फायदा कांग्रेस को मिला। लेफ्ट के वोट तो कांग्रेस को ट्रांसफर हो गए, लेकिन कांग्रेस के वोटर्स लेफ्ट की तरफ नहीं गए। इसका खामियाजा लेफ्ट को भुगतना पड़ा। कांग्रेस को इस चुनाव में दो सीटों की बढ़त मिली। हर राज्य में क्षेत्रीय दलों का अपना अलग वोटबैंक होता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर अलग। तीनों ही राज्यों में भाजपा अपनी पकड़ बना चुकी है। क्षेत्रीय दल भी अलग-अलग स्तर से कांग्रेस का वोट काट रहे हैं। क्षेत्रीय दलों के बढ़ते वर्चस्व के चलते भी कांग्रेस काफी कमजोर हो चुकी है। लगातार चुनावों में मिल रही हार से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं में मायूसी भी छा गई है। यही कारण है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जनता से भी दूर होते जा रहे हैं। इसका नुकसान भी कांग्रेस को चुनावों में उठाना पड़ा।

आंदोलन स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार को वादा याद दिलाने किया हवन अनुष्ठान

प्रदेश सरकार को चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करना चाहिए

कोरबा। कटघोरा स्थित आंदोलन स्थल पर कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने हवन कुंड बनाकर उसमें सरकार को सद्बुद्धि देने आहुतियां डाली। साथ ही चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को याद दिलाते हुए मांगों को पूरा करने कहा। उधर घंटाघर कोरबा में पीएमए सीएम के नाम पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर अपनी आवाज बुलंद करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जुटी हुई हैं।

कटघोरा स्थित बीईओ कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने बताया कि यह अनुष्ठान प्रदेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल व महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री अनिला भेड़िया के लिए किया गया। सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा करती है तो इससे सभी कार्यकर्ता सहायिकाओं के साथ उनके परिजनों का साथ मिलेगा। इससे सरकार का भी हित होगा। सरकार अगर उनकी मांगों को पूरी नहीं करती हैं तो इसका प्रतिकार उन्हें झेलना पड़ेगा। उधर कोरबा जिला मुख्यालय में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 28 जनवरी से बैठी कार्यकर्ता सहायिकाओं की प्रमुख वीणा साहू ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने से उन्हें उम्मीद जगी थी लेकिन 4 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद भी सरकार उनका ध्यान नहीं दे पाई है। मजबूरी में केन्द्र बंदकर आंदोलन करना पड़ रहा है। जिसका नुकसान केन्द्र से पोषित होने वाले हितग्राहियों को हो रहा है, इसके बाद भी सरकार नहीं ध्यान दे रही है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने बताया कि उनके हड़ताल में शामिल होने के कारण केन्द्रों में पिछले एक माह से अधिक समय से ताला लटक रहा है। जहां से पोषित होने वाले बच्चों को रेडी टू ईट फूड नहीं मिल पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि इससे बच्चों के साथ शिशुवती व गर्भवती महिलाओं का हित भी सरकार मारने में जुट गई है। यही कारण है उनकी मांगों को पूरा करना नहीं चाहती है सरकार। हकीकत भी यही है कि जिले में इन दिनों 90 फीसदी से अधिक अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन ठप पड़ गया है।

दुर्ग शहर के 600 कामगार हड़ताल पर, वार्डों में सफाई व्यवस्था ध्वस्त

■ आयुक्त कामगारो की मांग को जल्द पूर्ण करें : वोरा

दुर्ग। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इटंक के बैनरतले शहर के सफाई कामगार ड्रायवर, कम्प्यूटर ऑपरेटर व अन्य 600 कामगार के हड़ताल में जाने से 60 वार्डों में सफाई व अन्य व्यवस्था सुबह से ही ठप्प हो गई। लोगों के घरों व नुक्कडो से कचरा नहीं उठा। बजट सत्र में रायपुर जाने से पूर्व विधायक अरुण वोरा ने हड़तालियों के 8 सूत्रीय मांगो को लेकर दादा-दादी पार्क में एकत्रित कर्मचारियों से मिले और आयुक्त से चर्चा कर कर्मचारियों की मांग को जल्द पूर्ण करें व शासन स्तर के मांगो को नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया से हल करने का प्रयास की बात कर्मचारियों से की। कर्मचारियों की 8 सूत्रीय मांगो में प्रमुख निगम में कार्यरत् प्लेसमेंट सफाई कर्मियो के लिए ठेकेदारी प्रथा समाप्त, वेतन भविष्यनिधि एवं चिकित्सा सुविधा, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण कर्मियो को न्यूनतम मजदूरी व अन्य सुविधा प्रदान करने, रेलवे व जल विभाग में कार्यरत कर्मियो को भविष्यनिधि, चिकित्सा सुविधा व इंश्योरेशन, कम्प्यूटर ऑपरेटरो को एक ठेकेदार के अधीन की व्यवस्था, श्रमिक विरोधी कार्यवाही में रोक, एमबीबीएस डिग्रीधारी को स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति एवं कोरोना काल में कार्य करने वाले कर्मियो को एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। धरना स्थल पर एमआईसी मेम्बर श्रीमती जयश्री जोशी, पार्षद निर्मला साहू, राजेश शर्मा उपस्थित थे।

पीआईसी की बैठक में 42 एजेंडे पर सदस्यों ने लगाई मुहर

■ सभाकक्ष में नपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक

महासमुंद। प्रेसिडेंट इन कांउसिल की बैठक में 42 एजेंडों पर नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग सहित पीआईसी सदस्यों ने चर्चा की और सभी एजेंडे सर्वसम्मति से पारित किया।

नपाध्यक्ष सभाकक्ष में सोमवार को प्रेसिडेंट इन कांउसिल की बैठक हुई। बैठक में सभापति व उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार चंद्राकर, पवन पटेल निखिलकांत साहू, अमन चंद्राकर, डमरूधर मांझी, बबलू हरपाल, सरला गोलू मदनकार, सीएमओ डीएल वर्मन, लोक निर्माण विभाग के उप अभियंता दिलीप कश्यप, राजस्व प्रभारी दिलीप चंद्राकर, विद्युत प्रभारी सीताराम तेलक, गुमान सिंह ध्रुव, नौशाद बक्श, करण यादव, दुर्गेश कुंजेकर मौजूद रहे।

नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग की अध्यक्षता में हुई बैठक में 42 एजेंडे को पटल पर रखा गया, जिस पर अध्यक्ष सहित पीआईसी सदस्यों ने चर्चा की। इस दौरान नपाध्यक्ष महिलांग ने बारी-बारी सभी एजेंडे को सदस्यों को पढ़कर सुनाया। एजेंडे में जाति एवं मूल निवास की उद्घोषणा के संबंध में मिले आवेदनों पर प्रस्ताव, भवन भूमि नामांतरण, सितली नाला स्थित पालिका की दुकानों को किराए पर लेने के लिए मिले आवेदन, वार्ड 13, डिमांड पंजी में राजेश्वर प्रकाश टंडन के नाम के स्थान पर आवेदक अशोक कुमार टंडन का नाम दर्ज कराने, झैमलीभाटा वार्ड 2 के जैबून बी रेल्वे किनारे संबंधित वार्ड में अपने पुत्र के नाम से दर्ज डिमांड पंजी में नाम संशोधन एवं सुधार के लिए मिले आवेदन, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संपत्तिकर के वार्षिक भाड़ा मूल्य में वृद्धि करने, बिन्नी बाई सब्जी बाजार में पसरा व्यवस्था देने, पूर्व बकाया संपत्तिकर, जल कर की राशि को संबंधित बकायादारों से समझौता करने, अनुपस्थित आंगनबाड़ी सहायिकाओं को सेवा से पृथक किए जाने, 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुकी आंगनबाड़ी सहायिका को कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति करने, नगर पालिका परिषद में कर्मचारियों के पद निर्माण की स्वीकृति के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजने, नगर पालिका अधीनस्थ जेसीबी का मरम्मत किए जाने, वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुमानित बजट चार्टर्ड एकाउंटेंट से बनाए जाने, अध्यक्ष निधि व अन्य निधि से वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न वार्डों में कार्य कराए जाने के लिए वार्षिक निविदा आमंत्रण करने, वार्ड 9 से 15 तक विभिन्न निर्माण कार्य कराए जाने के लिए वार्षिक निविदा आमंत्रण, पार्षद निधि से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्ड 16 से 22 तक विभिन्न कार्य कराए जाने के लिए वार्षिक निविदा आमंत्रण, पार्षद निधि से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न कार्य वार्ड 23 से 30 तक कराए जाने के लिए वार्षिक निविदा आमंत्रण, मरम्मत संधारण मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्ड 1 से 10 तक कराए जाने वाले कार्य के लिए निविदा आमंत्रण, मरम्मत संधारण मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्ड 11 से 20 तक कार्य कराए जाने के लिए निविदा आमंत्रण, मरम्मत संधारण मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्ड 21 से 30 तक का कराए जाने वाले विभिन्न कार्य के लिए निविदा आमंत्रण, 15वें वित्त आयोग मद अंतर्गत वाहन उपकरण क्रय किए जाने, डॉ भीमराव अंबेडकर सर्व मांगलिक भवन का सौंदर्यीकरण किए जाने आदि की पाणध्यक्ष द्वारा 21 दिसंबर 2022 से 21 फरवरी 2023 तक विभिन्न कार्य के लिए पीआईसी की प्रत्याशा में दी गई।

पॉवर हाईट्स कॉलोनी के मकान में लगी भीषण आग

■ पुलिस और दमकल विभाग ने पाया काबू, सामान जलकल खाक

कोरबा। कोरबा में गर्मी बढ़ने के साथ ही दमकल विभाग की चुनौतियां भी बढ़ने लगी हैं। जिले के अलग-अलग इलाकों में रोज आग लग रही है। बीती रात घंटाघर-बुधवारी मार्ग पर मौजूद पॉवर हाईट्स रिहायशी कॉलोनी के एक मकान में आग लग गई। इस घटना के बाद पूरी कॉलोनी में अफरा-तफरी की स्थिती बन गई। सूचना पर पहुंची मानिकपुर पुलिस ने दमकल विभाग की सहायता से काफी मशक्कत के बाद आग को काबू में कर लिया।

कोरबा शहर में बीती रात घंटाघर बुधवारी मार्ग पर मौजूद पॉवर हाईट्स रिहायशी कॉलोनी में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब यहां दूसरे मंजिल पर स्थित एक मकान में आग लग गई। सुने मकान से धुआं उठता देख लोग सकते में आ गए। इसके साथ ही आग बुझाने की कोशिशों में जुट गए। लोगों की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाने में सफलता मिली। बताया जा रहा है, कि घटना के दौरान मकान के मालिक जसप्रीत फ्लोरा शहर की ओर गए थे। घरेलू उपकरणों में हुए शार्ट सर्किट को घटना की वजह माना जा रहा। कॉलोनी निवासी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि वह भी ऊपर फ्लोर पर रहते हैं सामने वाले घर के खिड़की से धुआं उठता देख मकान मालिक और दमकल वाहन को सूचना दी। जहां मौके पर दमकल वाहन पहुंच घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कॉलोनी के ऊपर फ्लोर होने के चलते हैं दमकल वाहन को काफी मशक्कत करनी पड़ी तब जाकर आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि मकान मालिक जसप्रीत फ्लोरा व्यवसाई है और टीपी नगर में मकान और होटल दोनों है परिवार वहीं गया हुआ था जब सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे तब तक पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था। आग बेडरूम में लगी थी, जो शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगना बताया जा रहा है दो एसी, कपड़े और अलमारी पूरी तरह जल चुकी थी। घटना की सूचना पर मानिकपुर चौकी पुलिस स्टाफ भी मौके पर पहुंची, जिन्हेंने आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों के साथ घंटों प्रयास किया।

निगम ने की गोबर पेंट से नवनिर्मित सामुदायिक भवन की पोताई

कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अभी हाल ही में बनाए गए सामुदायिक भवन की पेंटिंग गोबर पेंट से कराई गई हैं, यह सामुदायिक भवन गोबर पेंट से पेंटिंग होने वाला जिले का शायद पहला भवन होगा। वहीं आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निगम के सभी नवनिर्मित भवन अब अनिवार्य रूप से गोबर पेंट से ही पोते जाएं, वहीं पुराने भवनों की जब पोताई का कार्य हो तो अनिवार्य रूप से केवल गोबर पेंट ही उपयोग में लाया जाए।

■ आयुक्त का निर्देश-निगम के सभी भवन अब अनिवार्य रूप से गोबर पेंट से ही पोते जाएं

यहां उल्लेखनीय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अनोखी पहल करते हुए गाय के गोबर से बने जैविक पेंट से ही राज्य के सरकारी भवनों, स्कूलों और छात्रावासों की पोताई किए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके परिपालन में प्रदेश के शासकीय भवनों की पोताई गाय के गोबर से बने पेंन्ट्स से की जा रही है। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अभी हाल ही में बनाए गए सामुदायिक भवन की पेंटिंग पोताई का कार्य गोबर से बने पेंट से कराया गया है, गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी क्योंकि गोठानों में गोबर पेंट के निर्माण कार्य में स्थानीय महिलाएं व महिला स्वसहायता समूह जुड़े हुए हैं, यहाँ यह उल्लेख करना लाजिमी होगा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में दो वर्ष पहले गोधन न्याय योजना की शुरूआत की थी, जिसके तहत गोठानों व गोबर खरीदी केन्द्रों में पशुपालकों व किसानों से 02 रूपये प्रतिकिलो के हिसाब से गोबर और 04 रूपये प्रतिकिलो के हिसाब से गौमूत्र खरीदा जा रहा है, राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप गोबर से किए जा रहे पूर्व के उत्पादों के अतिरिक्त अब गोबर पेंट का निर्माण भी किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

प्रेमलता ने सोंदूर जलाशय से पानी छोड़ने की मांग की

नगरी। वरिष्ठ भाजपा नेत्री एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती प्रेमलता नागवंशी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन योजना का धमतरी जिले में अभी तक केवल सत्ताईस प्रतिशत कार्य हुआ है जो नहीं के बराबर है किसी ग्राम में पाइप लाइन बिछा है तो किसी ग्राम में टंकी का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है पाइप लाइन के कारण गांव की सड़कों का हाल बुरा है ठेकेदार कई गांवों के कार्य को अधूरा छोड़ कर भाग गए है सरपंचों से जानकारी लेने पर पता चला है कि ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल रहा है ऐसे में क्या इस वर्ष भरी गर्मी में लोगों को पानी के लिए दिक्कतें आएगी। नदी नाले लगभग सूख गए हैं लेकिन राज्य की भूपेश सरकार के कानो में जुं तक नहीं रेंग रही है बांधों में लबालब पानी होने के बाद भी देऊरपारा एनीकेट सूखा पड़ा है बोरवेल सूखने लगे हैं वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है मैं क्षेत्रवासियों के लिए पानी की मांग करती हूं तुरंत ही सोंदूर जलाशय से पानी छोड़ा जाये और जल जीवन मिशन के कार्यों में गति लाया जाये।

आज विधानसभा घेरेंगी रसोइया महिलाएं

महासमुंद। कलेक्टर दर पर मानदेय की मांग पूरा करने के लिए विधानसभा का घेराव करने रसोइया संघ मंगलवार को राजधानी के लिए रवाना हुए। इधर, हड़ताल की वजह से अब स्कूलों में मध्याह्न भोजन भी प्रभावित हो गया है। रैली दोपहर 12 बजे पटवारी कार्यालय से निकली। रसोईया सिर में काली हंडी लेकर निकलीं। 3 को विधानसभा का घेराव करेंगी। रसोइया संघ की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे ने बताया कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (मिड-डे मील योजना) अंतर्गत प्रदेश के 33 जिलों के 45610 शालाओं में 87026 रसोइया भोजन बनाने के लिए नियोजित किया गया है। रसोइया एवं रसोइया सह-सहायिका का मानदेय वर्तमान में 1500 प्रति माह है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही देय होता है। वर्तमान सरकार के जनघोषणा-पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ स्कूल के अन्य कर्मचारियों को कलेक्टर दर के अनुसार वेतन दिए जाना उल्लेख है। वर्तमान में दिया जाने वाला मानदेय अत्यंत कम है।

जनपद अध्यक्ष से आदिवासी ध्रुव गोंड समाज के लोगों ने मुलाकात की

नगरी। आदिवासी ध्रुव गोंड समाज भोथली के सामाजिक जन जनपद पंचायत कार्यालय नगरी पहुँचे। जहाँ उन्होंने ने जनपद पंचायत नगरी के अध्यक्ष दिनेश्वरी नेताम से मुलाकात कर भोथली में आदिवासी ध्रुव गोंड समाज के लिये सामुदायिक भवन निर्माण की मांग किये। इस बाबत समाज के लोगों ने जनपद अध्यक्ष को लिखित आवेदन भी दिया। आवेदन में आदिवासी ध्रुव गोंड समाज भोथली के सामाजिक जनों ने जिक्र करते हुए लिखा है कि उनके द्वारा बीते 15 वर्षों से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को सामुदायिक भवन निर्माण के लिये मांग कर रहे हैं। पर आज तक उनकी मांगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं जनपद अध्यक्ष नगरी दिनेश्वरी नेताम ने समाज के लोगों को आश्वश्त करते हुए कहा कि आगामी बजट में सामुदायिक भवन देने की बात कही है। इस दौरान भोथली सरपंच दुर्गेश्वरी पालेश्वर, रामस्वरूप नेताम अध्यक्ष ध्रुव गोंड समाज भोथली, गीता बाई अध्यक्ष भोथली, युवा अध्यक्ष कृष्णा ध्रुव, यशवंत ध्रुव, सरस्वती नेताम आदि उपस्थित थे।

कछारडीह के रामायण समारोह में पहुंचे विमल चोपड़ा

महासमुंद। कछारडीह के ग्रामीणों द्वारा आयोजित रामायण कार्यक्रम में पूर्व विधायक एवं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक डॉ. विमल चोपड़ा एवं भाजपा नेता शम्मी सलूजा शामिल हुए।

डॉ. चोपड़ा ने कहा कि रामायण में हमारे जीवन का सार है। किसी भी परिस्थिति से हम कैसे बाहर आएं यह सीख भी हमें रामायण से मिलती है। पारिवारिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों से अपने परिवार को बिना तोड़े कैसे एक-दूसरे के साथ रहा जा सकता है यह बात भी रामायण में निहित है। रामायण में भाई-भाई का प्रेम, पिता-पुत्र का प्रेम सम्मान करना, रामायण के एक -एक व्यक्ति के चरित्र में रिश्तों की कद्र करना सिखाता है। डॉ. चोपड़ा ने शराबबंदी एवं नशाबंदी का बिगुल फूंकते हुए लोगों से कहा कि कांग्रेस की यह सरकार शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आयी। पर आज छत्तीसगढ़िया लोगों को शराब पिलाकर अपनी जेब भरने और कांग्रेस के एटीएम में पैसा डालने का काम कर रही है।

कोल माइंस में लगी आग से काफी कोयला जलकर खाक

कोरबा। कोरबा जिले के एसईसीएल गेवरा कोल माईंस के कोल स्टॉक में मंगलवार को लगी भीषण आग पर बुधवार तड़के काबू पा लिया गया। गेवरा के आनंद वाटिका कोल स्टॉक में लगी आग पर 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आगू पाया जा सका। आग लगने के कारण कोल इंडिया को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इधर पूरे मामले में प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बारे में जब एसईसीएल के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उनका मोबाइल बंद मिला। वहीं घटनास्थल पर मौजूद अधिकारी इस संबंध में कुछ भी कहने से बचते नजर आए। बताया जा रहा है कि आग काफी समय से लगी हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने उस पर संज्ञान नहीं लिया और आग फैलती चली गई। तब जाकर आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कोल स्टॉक का काफी हिस्सा धू-धूकर जल चुका था। इससे पहले भी कुसमुंडा गेवरा दीपका और मानिकपुर के कोल माईंस में आग लग चुकी है।

वार्डवासियों के हाथों हुआ आरसीसी नाला का भूमिपूजन

धमतरी। महापौर विजय देवांगन द्वारा आम नागरिकों को सुविधा में ध्यान रखते हुए विंध्यवासिनी वार्ड मे कारगिल चौक से बैला बाजार तक नाली क्षतिग्रस्त दयनीय स्थिति में थी जिसके मरम्मत कार्य के लिए वार्ड पार्षद/एमआईसी सदस्य कमलेश सोनकर एवं वार्डवासियों के द्वारा वर्षों से लगातार मांग की जा रही थी। जिसे महापौर विजय देवांगन ने जनता के वादे को पुरा करते हुए आर.सीसी नाला(लागत राशि-20.40 लाख) का भूमि पूजन महापौर विजय देवांगन, एमआईसी सदस्य राजेश ठाकुर,वार्ड पार्षद कमलेश सोनकर,केंद्र कुमार पेंदरिया,ज्योति वाल्मीकि,जिला कांग्रेस

महामंत्री आलोक जाधव, पार्षद दीपक सोनकर एवं वार्डवासियों के हाथो किया गया।

शहर के चौमुखी विकास के साथ साथ विंध्यवासिनी वार्ड में महापौर विजय देवांगन द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों एवं बरसों से रही समस्या का समाधान करवाने के लिए वार्डवासीयों ने नगर निगम के महापौर विजय देवांगन, सभापति अनुराग मसीह,आयुक्त विनय कुमार पोयाम,लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष राजेश ठाकुर,वार्ड पार्षद एवं एमआईसी सदस्य कमलेश सोनकर और नगर पालिक निगम धमतरी का धन्यवाद कर आभार व्यक्त किये।

महापौर विजय देवांगन ने कहा कि उक्त स्थान में जलभराव की स्थिति जर्जर नाली होने कारण निर्मित हो रही थी इसलिए जो पानी भरता है इस नाला के निर्माण हो जाने से आगे बढ़ सकेगा और इस जगह में पानी भराव की स्थिति कम हो जायेगी । रेनिश सिस्टम सुधारने का जो नगर निगम का प्रयास है उसके अंतर्गत इस आरसीसी नाला की स्वीकृति प्रदान की गई है जो तत्काल कार्य प्रारंभ होगा जिसकी आज भूमि पूजन की गई है आगे कहा कि संपूर्ण नाली निर्माण कार्य मास्टर प्लान के तहत कराया जा रहा है,जिससे यहां के रहवासियों को जल भराव मे कमी आयेगी। लोक निर्माण विभाग अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भूमिपूजन के बाद निर्माणकर्ता ऐजेंसी से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भूमिपूजन के बाद कार्य आरंभ करने में विलंब न करे। समय सीमा में नाला निर्माण कार्य पूर्ण करे,जिससे वार्डवासियों को जल भराव से राहत मिले।

बेहतर शाखकर्तन से उच्च क्वालिटी का मिलेगा तेंदूपत्ता

■ कार्यशाला का संसदीय सचिव ने किया शुभारंभ

महासमुंद। संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने तेंदूपत्ता सीजन 2023 के लिए वन विभाग के वन विद्यालय के सभागार में आयोजित शाखकर्तन कार्यशाला का पूजा अर्चना कर विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने संग्राहकों को तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य से अधिक लाभ मिले, इसके लिए सही व बेहतर तकनीक से शाखकर्तन करने जोर दिया।

बुधवार को तेंदूपत्ता सीजन 2023 के लिए वन विभाग के वन विद्यालय के सभागार में शाखकर्तन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर थे। अध्यक्षता लघु वनोपज संघ के जिलाध्यक्ष प्रमोद चंद्राकर ने की। विशेष अतिथि के रूप में कृषि उपज मंडी अध्यक्ष हीरा बंजारे, बीज अनुसंधान समिति के संचालक दाउलाल चंद्राकर, जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री संजय शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष खिलावन बघेल, लघु वनोपज संघ के उपाध्यक्ष अमर कुमार नाग, संचालक सदस्य बसंत सिन्हा, रामजी ध्रुव, भागीरथी मार्कंडे मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने कहा कि बेहतर तरीके से शाखकर्तन किए जाने से उच्च क्वालिटी का तेंदूपत्ता मिलेगा। जो अधिक दाम में बिकता है और इससे संग्राहकों को बोनस भी ज्यादा मिलेगा। लिहाजा शाखकर्तन के कार्य को प्रमुखता के साथ किया जाना चाहिए। संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने कहा कि लघु वनोपज संग्राहक परिवारों के हितों के लिए भूपेश सरकार निरंतर काम कर रही है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

रक्षामंत्री ने कर्नाटक में विजय संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ

बेंगलुरु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को कर्नाटक के बेलगावी में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से राज्य में भाजपा सरकार बनाने की अपील की। आपको बता दें कि कर्नाटक में इस साल विधानसभा के चुनाव होने है। भाजपा वहां सत्ता में है और दोबारा वापसी के लिए पूरी मेहनत कर रही है। चुनावी रणनीति को धार देने के लिए भाजपा की ओर से राज्य में विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं मानता हूं कि कर्नाटक की धरती सदैव वीरता और शौर्य की साक्षी रही है। राजनाथ ने कहा कि इस धरती से सूर्य वीरों ने जन्म लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये विजय संकल्प यात्रा है और आप सब संकल्प लीजिए कि एक बार फिर से 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाएंगे और नए कर्नाटक का निर्माण करेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और राज्य भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील भी मौजूद रहें।

प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की कमेटी करेगी निर्वाचन आयुक्त का चुनाव

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नए नियम दिए। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के समान, सीईसी/ईसी अब एक समिति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जिसमें प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने आदेश दिया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। न्यायमूर्ति केएम जोसेफ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि इस प्रथा को तब तक लागू किया जाएगा जब तक कि संसद द्वारा इस संबंध में एक कानून नहीं बनाया जाता है। जस्टिस केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार की एक संविधान पीठ भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करने वाली याचिकाओं का एक बैच तय कर रही थी।

कांग्रेस को प्रधानमंत्री पद का मोह छोड़ना पड़ेगा : अब्दुल्ला

चेन्नई। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने विपक्षी एकता की बात करते हुए कहा कि अगर सभी दल इकट्ठा होकर साथ मंच साझा करें तो केंद्र की मौजूदा सत्ताधारी एनडीए को सत्ता से दूर धकेला जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के जन्मदिन पर कहा कि अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल साझा गठबंधन करके चुनाव जीतते हैं तो मौजूदा तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन में भी प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि अगर एनडीए को सत्ता से बाहर करना है तो उसके लिए कांग्रेस को प्रधानमंत्री पद का मोह छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस केवल 2024 के लोकसभा चुनाव की जीत पर ध्यान केंद्रित करे, बिना किसी पद की चाहत के। मैं तमाम दलों समेत कांग्रेस के खड़गे से भी कहूंगा कि भूल जाइए कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा।

तेलंगाना में भाजपा अपने दम पर देगी केसीआर को टक्कर

हैदराबाद। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा ऐलान किया है। तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंदी संजय ने स्पष्ट किया है कि पार्टी इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले उतरेगी। बंदी संजय कुमार ने इस बात की घोषणा की कि भाजपा अपने दमखम पर सूबे में सत्ताधारी दल भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और उसके अगुवा के चंद्रशेखर राव को चुनौती देगी। बंदी संजय ने यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के साथ मंगलवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद बुधवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भाजपा महिला मोर्चा की बैठक में कही। संजय ने तेलंगाना भाजपा को दो टूक कहा कि दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि भाजपा बिना किसी के साथ गठबंधन किये राज्य विधानसभा का चुनाव अपनी लोकप्रियता पर लड़े। उन्होंने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का पूरा भरोसा है कि पार्टी केसीआर को हराकर सत्ता में आएगी।

राउत की टिप्पणियों के हर पहलू के समझने की जरूरत

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को मंजूरी देने पर बृहस्पतिवार को आपत्ति जताई। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भाजपा के विधायक राहुल कुल की अध्यक्षता में बुधवार को 2023-24 के लिए सदन की 15 सदस्यीय विशेषाधिकार समिति का गठन किया था। समिति में राकांपा के तीन, कांग्रेस के दो, सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन करने वाले दो निर्दलीय विधायक, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के दो और भाजपा के छह विधायक शामिल हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े के किसी विधायक को समिति में जगह नहीं मिली। दरअसल, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत के विधानमंडल को कथित तौर पर चोर मंडल कहा था, जिसको लेकर सदन में हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को मंजूरी दे दी थी।

विदेश मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित

भारत ग्लोबल साउथ की आवाज

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के संगठन जी-20 के विदेश मंत्रियों की बैठक गुरुवार को सुबह 9.20 मिनट पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में शुरू हुई। बैठक के शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते दिनों तुर्की व सीरिया में आए भयंकर भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए एक मिनट का मौन धारण किया गया है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ बैठक की आधिकारिक शुरुआत हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए भारत पहुंचे जी20 देशों के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह बैठक एकता, एक उद्देश्य और कार्रवाई की एकता की जरूरतों को बल देता है। मुझे उम्मीद है कि आज की आपकी बैठक आम और ठोस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आने की भावना को दर्शाएगी। जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है।

हम सभी को स्वीकार करना चाहिए कि बहुपक्षवाद आज संकट में

जी-20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी को यह स्वीकार करना चाहिए कि बहुपक्षवाद आज संकट में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई वैश्विक शासन की वास्तुकला दो कार्यों को पूरा करने के लिए थी। उनमें पहला- प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करके भविष्य के युद्धों को रोकना था जबकि जबकि दूसरा सामान्य हित के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। पीएम ने कहा वित्तीय संकट, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और युद्धों के पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से स्पष्ट है कि वैश्विक शासन

अपने दोनों जनादेशों में विफल रहा है।

प्रभावित लोगों की सुने बिना कोई भी समूह वैश्विक नेतृत्व का दावा नहीं कर सकता

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, वर्तमान में कोई भी समूह अपने निर्णयों से सर्वाधिक प्रभावित लोगों की बात सुने बिना वैश्विक नेतृत्व का दावा नहीं कर सकता। यह बैठक गहरे वैश्विक विभाजन के समय में हो रही है। विदेश मंत्रियों के रूप में ये स्वाभाविक है कि आपकी चर्चा भू-राजनीतिक तनावों से प्रभावित होगी। पीएम बोले- दुनिया विकास, आर्थिक लचीलापन, आपदा लचीलापन, वित्तीय स्थिरता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, विकास की चुनौतियों को कम करने के लिए जी20 की ओर देख रही है। इन सभी में जी20 में आम सहमति बनाने और ठोस परिणाम देने की क्षमता है।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में साथ ही कहा कि जी-20 देशों के अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि जी20 संगठन के देश आपसी मतभेद को भुला कर महत्वाकांक्षी और बेहतर नतीजे को ध्यान में रख कर कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि हमें जो मुद्दे आपसी में संगठित करते हैं उस पर ध्यान देना होगा, न कि उन मुद्दों पर जो विभेद पैदा करते हैं।

आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत-इटली साथ

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इटली की अपनी समकक्ष ज्यॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाने पर विचारों का आदान-प्रदान भी किया। इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारे राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं और हमने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमने अपने आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया। हमारा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत में निवेश के अपार अवसर खुल रहे हैं।

पीएम ने कहा कि हमने अक्षय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, आईटी, अर्धचालक, दूरसंचार, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और इटली के बीच एक स्टार्टअप ब्रिज की स्थापना की आज घोषणा हो रही है, जिसका हम स्वागत करते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और इटली कंधे से कंधा मिला कर चल रहे हैं। हमने इस सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शुरुआत से ही भारत ने यह स्पष्ट किया है कि इस विवाद को केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिये ही सुलझाया जा सकता है। भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।

हार पर बोले हेमंत सोरेन, जनादेश स्वीकार, मुख्य मैच तो अभी बाकी है

नई दिल्ली। हेमंत सोरेन ने कहा कि राजनीति में जो आंतरिक और बाहरी व्यवस्था है उसे लोग जानते ही हैं। जनादेश को स्वीकार करते हैं...मुख्य मैच तो अभी बाकी है। वहीं, पूर्व सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुबर दास ने कहा कि रामगढ़ में ह्रदय की जीत पर सभी देवतुल्य मतदाताओं, जुझारू कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिवादन।

त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में चुनावी नतीजों के साथ ही 5 राज्यों की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव के भी नतीजे आ गए हैं। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। झारखंड के रामगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा समर्थित आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने जीत हासिल की है। सुनीता चौधरी ने 21970 मतों के अंतर से यूपीए समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को हराया है। इससे अब भाजपा के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर उपचुनाव के नतीजों को लेकर यूपीए सरकार का नेतृत्व कर रहे हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा

कि जनादेश स्वीकार है। मुख्य मुकाबला अभी बाकी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक हेमंत सोरेन ने कहा कि राजनीति में जो आंतरिक और बाहरी व्यवस्था है उसे लोग जानते ही हैं। जनादेश को स्वीकार करते हैं. मुख्य मैच तो अभी बाकी है। वहीं, पूर्व सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुबर दास ने कहा कि रामगढ़ में ह्रदय की जीत पर सभी देवतुल्य मतदाताओं, जुझारू कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिवादन। उन्होंने कहा कि यह प्रचंड विजय राज्य की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार की विदाई की शुरुआत है। युवा, महिला, किसान, मजदूर, आदिवासी, पिछड़े, वंचितों समेत सभी झारखंडवासियों को धोखा देनेवालों को यह जनता का जवाब है। मतगणना पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने कहा कि भाजपा के साथ मिलकर उपचुनाव में उतरी आजसू पार्टी को 1,15,669 वोट मिले जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस को 93,699 मत मिले। मतों की गिनती सुबह आठ बजे शुरू हुई थी। इस निर्वाचन क्षेत्र में 27 फरवरी को उपचुनाव हुआ था जिसमें 67.96 प्रतिशत मतदान हुआ था। वैसे तो 14 निर्दलीय समेत 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आजसू के बीच था। कांग्रेस विधायक ममता देवी को आपराधिक मामले में दोषसिद्ध होने पर विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराये जाने के बाद यह उपचुनाव कराया गया।

उपचुनाव ने पार्टी के लिए थोड़ी खुशियां लाई

नई दिल्ली। पूर्वोत्तर के चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन उसकी अपनी उम्मीदों से काफी नीचे था, केवल तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के उपचुनावों के नतीजों ने उसे कुछ खुशी दी। हालांकि त्रिपुरा और मेघालय विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन पार्टी त्रिपुरा में कुछ सीटों पर जीत हासिल करके और मेघालय विधानसभा में कुछ उपस्थिति बनाए रखकर कुछ उम्मीद कर सकती है। . नागालैंड में पार्टी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मेघालय में कांग्रेस 2018 के चुनावों में 21 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन इस बार एक भी विधायक के बिना चुनाव में उतरी। नवंबर 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा सहित 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में चले गए। अन्य लोग भी कांग्रेस छोड़ से कूद गए और अन्य दलों में शामिल हो गए। कांग्रेस त्रिपुरा में तीन सीटों पर आगे चल रही थी और मेघालय में 5 सीट जीत दर्ज की है। जबकि नगालैंड में उसका खाता भी नहीं खुला है। मेघालय में कांग्रेस बड़ी संख्या में नए चेहरों के साथ चुनाव में उतरी थी। इसके 60 उम्मीदवारों में से 47 की उम्र 45 साल से कम थी। त्रिपुरा में पिछली बार कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इस बार वह तीन सीटों पर आगे है। पार्टी ने जिन 13 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से पांच से आठ सीटें जीतने की उम्मीद की थी। माकपा ने कांग्रेस नेतृत्व से कहा था कि वाम दल 25 से 29 सीटें जीतेंगे। लेकिन लेफ्ट, जिसके पास पिछली बार 16 सीटें थीं, अब तक केवल 11 सीटों पर आगे चल रहा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को हराने और सत्तारूढ़ दल से मुर्शिदाबाद जिले की सागरदिघी सीट छीनने के लिए तैयार है। टीएमसी 2011 से सीट जीत रही थी।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 76 रन का लक्ष्य रखा

इंदौर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 76 रन का लक्ष्य रखा है। टीम इंडिया की दूसरी पारी 163 रन पर सिमट गई। पहली पारी में भारत ने 109 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 197 रन बनाए थे। कंगारुओं को 88 रन की बढ़त मिली थी। भारत ने दूसरी पारी में 163 रन बनाए और इस तरह 75 रन की बढ़त हासिल की और 76 रन का लक्ष्य रखा। मोहम्मद सिराज के रूप में भारत का आखिरी विकेट गिरा। इसी के साथ अंपायर ने दूसरे दिन का खेल खत्म करने की भी घोषणा कर दी। अब ऑस्ट्रेलिया को अगले तीन दिन में 76 रन बनाने हैं।

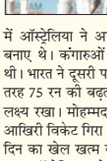

इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 197 रन पर समेट दिया। आज कंगारुओं ने चार विकेट पर 156 रन से आगे खेलना शुरू किया। तब पीटर हैंड्सकॉम्ब और कैमरन ग्रीन क्रीज पर थे। इसके बाद करीब एक घंटे तक इन दोनों ने कोई विकेट नहीं गिरने दिया। हालांकि, इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ खेल हो गया। 27 मिनट के अंदर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के अगले छह विकेट ले लिए। भारत ने 34 गेंदों के अंदर और 11 रन बनाने में ऑस्ट्रेलिया का छह विकेट गिरा दिए। 71वें ओवर की आखिरी गेंद पर अश्विन ने पीटर हैंड्सकॉम्ब के रूप में ऑस्ट्रेलिया को पांचवां झटका दिया था। इसके बाद 77वें ओवर की तीसरी गेंद पर 197 रन पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी सिमट गई। आज अश्विन और उमेश यादव ने तीन-तीन विकेट लिए। उमेश ने कैमरन ग्रीन (21) को एलबीडब्ल्यू किया। इसके मिचेल स्टार्क और टॉड मर्फी (0) को क्लीन बोल्ड किया। वहीं, हैंड्सकॉम्ब (19) के अलावा अश्विन ने एलेक्स कैरी (3) को आउट किया। फिर नाथन लियोन (5) को आउट कर पूरी पारी को 197 रन पर समेट दिया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/ प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 501 अंक टूटा, निफ्टी 17,400 के नीचे आया

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 502 अंक टूट गया, वहीं निफ्टी 129 अंक फिसलकर 17,400 के नीचे आ गया। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक भी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 501.73 अंक यानी 0.84 फीसदी नुकसान के साथ 58,909.35 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ऊंचे में 59,423.79 तक गया और नीचे में 58,866.26 तक आया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (ह्रस्व) के निफ्टी में भी 129 अंक यानी 0.74 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी कारोबार के अंत में 17,321.90 अंक पर बंद हुआ।

सेबी ने 31 इकाइयों को कारोबार से प्रतिबंधित किया

नईदिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को एक्टर अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी और साधना ब्रॉडकास्ट के प्रोमोटर्स समेत 31 इकाइयों को प्रतिभूति बाजार में कारोबार से प्रतिबंधित कर दिया है। नियामक ने यह कदम यूट्यूब चैनल पर निवेशकों को कंपनी के शेयर खरीदने का सुझाव देने वाले भ्रामक वीडियो डालने के मामले में उठाया है। कंपनी के जिन प्रवर्तकों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया गया है उनमें श्रेया गुप्ता, गौरव गुप्ता, सौरभ गुप्ता, पूजा अग्रवाल और वरुण एम शामिल हैं। इसके अलावा नियामक ने यूट्यूब चैनल पर भ्रामक वीडियो डालने के बाद इन इकाइयों को हुए गैरकानूनी लाभ के 41.85 करोड़ रुपये भी जब्त करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत : अदाणी ग्रुप

नईदिल्ली। संकट में फंसे उद्योगपति गौतम अदाणी ने सुप्रीम कोर्ट के हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की समयबद्ध जांच के आदेश का स्वागत किया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने समूह की कंपनियों के शेयरों में आई हालिया गिरावट की जांच के लिए समिति के गठन का भी आदेश दिया है। इसपर अपनी प्रतिक्रिया में अदाणी ने गुरुवार को कहा कि इससे चीजें स्पष्ट होंगी और 'सच्चाई की जीत' होगी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के आदेश के बाद अदाणी ने ट्वीट किया, "अदाणी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है। इससे चीजें समयबद्ध तरीके से अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगी। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को हिंडनबर्ग के अदाणी ग्रुप पर आरोपों को लेकर दो माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया।

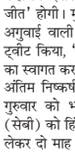

जैनेटिक मैपिंग के क्षेत्र में मुकेश अंबानी की एंट्री

नईदिल्ली। मुकेश अंबानी अब जेनेटिक मैपिंग के कारोबार में भी एंट्री ले रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज प्रा. के सीईओ रमेश हरिहरन ने कहा है कि एनर्जी से ई-कॉमर्स तक में सक्रिय समूह 12,000 रुपये (145 डॉलर) के जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के साथ कुछ हफ्तों के भीतर इस क्षेत्र में कदम रख देगा। स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज प्रा. ने ही इस प्रोडक्ट को विकसित किया है। जिसे हाल ही में रिलायंस ने खरीदा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से अंबानी का डेटा की दुनिया में कदम रखने का प्लान भी कामयाब होता दिख रहा है। हरिहरन ने कहा, यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे सस्ता जीनोमिक प्रोफाइल होगा। हम बेहतर प्राइस के साथ बाजार में उतरने जा रहे हैं। इससे हमें हेल्थकेयर के क्षेत्र में एक अच्छा बिजनेस खड़ा करने का मौका मिला है।

कम हो चीन से व्यापार असंतुलन

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

चीन से लगातार बढ़ता व्यापार असंतुलन देश की एक बड़ी आर्थिक चिंता का कारण बन गया है। इस पर विभिन्न स्तरों पर विचार मंथन हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 फरवरी को एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में कहा कि चीन से व्यापारिक असंतुलन की गंभीर चुनौती के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, देश का उद्योग-कारोबार भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कल-पुर्जे सहित संसाधनों के विभिन्न स्रोत और मध्यस्थ विकसित करने में प्रभावी भूमिका नहीं निभायी है।

देश की बड़ी कंपनियां शोध एवं नवाचार में भी पीछे हैं। हाल ही में 17 फरवरी को वाणिज्य मंत्रालय ने भारत-चीन व्यापार के अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 10 महीनों के आयात-निर्यात के जो आंकड़े जारी किये हैं, उसके मुताबिक इस अवधि में चीन से होने वाले आयात में नौ फीसदी का उछाल आया है। इस अवधि में चीन को किये जाने वाले निर्यात में 34 फीसदी की भारी कमी आयी है।

वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 10 महीनों में भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 13.91 फीसदी है। इस अवधि में भारत ने कुल 83.76 अरब डॉलर का आयात चीन से किया है, जबकि इसी अवधि में भारत ने चीन को केवल 12.20 अरब डॉलर का निर्यात किया है। भारत द्वारा किये जाने वाले निर्यात में चीन की हिस्सेदारी केवल 3.30 फीसदी है। स्थिति यह है कि इस समय जहां दुनिया के 150 से अधिक देशों में भारत से होने वाले निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं चीन को निर्यात में लगातार कमी होती दिख रही है। पिछले कुछ सालों में चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ा है, हिंसक झड़पें भी हुई हैं, फिर भी व्यापार में भारत की चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष

गोयल ने दिसंबर 2022 में राज्यसभा में कहा कि 2004-05 में भारत और चीन के बीच 1.48 अरब डॉलर का व्यापार घाटा था, जो 2013-14 में 36.21 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इन वर्षों में चीन से आयात भी दस गुना से अधिक हो गया है। इन वर्षों में पूरा देश घटिया चीनी उत्पादों से भर गया और भारत बहुत कुछ चीनी सामानों पर निर्भर होता गया। उल्लेखनीय है कि चीन से आने वाले सामान में विभिन्न उद्योगों के उत्पादन में काम आने वाली चीजें, दवाइयों के कच्चे माल, दवाइयां, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान, पशु या वनस्पति वसा, अयस्क, लावा और राख, खनिज ईंधन, अकार्बनिक तथा कार्बनिक रसायन, उर्वरक, रंगाई के अर्क, विविध रासायनिक उत्पाद, प्लास्टिक, कागज और पेपरबोर्ड, कपास, कपड़े, जूते, कांच तथा कांच के बने पदार्थ, लोहा और इस्पात, तांबा, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, फर्नीचर आदि शामिल हैं। निश्चित ही, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बार-बार स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और वोकल फॉर लोकल मुहिम के प्रसार से स्थानीय उत्पादों की खरीद को बढ़ावा मिला है।

यह महत्वपूर्ण है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में 24 सेक्टरों में मैनुफैक्चरिंग को प्राथमिकता के साथ बढ़ाया जा रहा है। चीन से आयातित दवाई, रसायन और अन्य कच्चे माल का विकल्प तैयार करने के लिए पिछले दो वर्ष में सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) स्कीम के तहत 14 उद्योगों को करीब दो लाख करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। उम्मीद है कि जिस तरह भारतीय खिलौना उद्योग ने चीन से आयात में भारी कमी कर देश और दुनिया को अचंभित किया है, उसी तरह उद्योग-कारोबार के अन्य क्षेत्रों में भी चीन से आयात घटाने और चीन को निर्यात बढ़ाने के नये अध्याय लिखे जायेंगे। फिर से देश के करोड़ों लोग स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के नये संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। साथ ही, देश के बाजार में चीन के वर्चस्व को तोड़ने के लिए उद्यमी और कारोबारी शोध और नवाचार को अपनाते हुए, चीनी कच्चे माल और चीन से संबंधित अन्य आयातित सामानों के स्थानीय विकल्प प्रस्तुत करने की डगर पर आगे बढ़ेंगे। साथ ही, देश के उद्योग-कारोबार जगत के द्वारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) का अधिकतम लाभ लेते हुए इसके कारगर क्रियान्वयन से चीन से आयात का प्रभुत्व कम करने के लिए अधिकतम प्रयास किये जायेंगे। इससे चीन से आयात कम होंगे, चीन को निर्यात बढ़ेगा और चीन से व्यापार घाटे में कमी लायी जा सकेगी। इस प्रकार, चीन पर भारतीय बाजार की निर्भरता कम हो सकेगी।

जनता के मुद्दों पर उदासीन है विपक्ष?

ललित गर्ग

वह चाहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण हो, चाहे जन प्रतिनिधियों का मंच हो या सरकारी विज्ञप्तियां या फिर सत्तापक्ष के सांसदों-मंत्रियों के बयान, बार-बार उपलब्धियों के चमकदार आंकड़े देश के आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होने, दुनिया की महाशक्ति बनने एवं विकास के नये आयामों के सृजन की बातें कर रहे हैं। निश्चित ही देश आजादी के अमृत-काल में बेहतर हुआ है और लगातार बेहतर हो रहा है। इस बात पर खुशी प्रकट की जा सकती है कि जब दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियां दम तोड़ रही हैं, तब भारत तमाम विपरीत स्थितियों में स्वयं को न केवल संभाले हुए है बल्कि विकास एवं आर्थिक उन्नति के नये मानक गढ़ रहा है। जिस देश के हम गुलाम रहे, उसे पछाड़ कर हमने दुनिया में पांचवां दर्जा हासिल कर लिया और बहुत जल्दी आशावादी देश-निर्माताओं के अनुसार हम दुनिया में तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने जा रहे हैं। लेकिन इन सुनहरे दृश्यों के बीच अनेक ऐसी विषमताएं एवं विसंगतियां भी हैं जो हमें आत्म-मंथन को प्रेरित करती हैं। जिनमें महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी, पर्यावरण असंतुलन, बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं नित-नये कानूनों एवं व्यवस्थाओं के बीच दम तोड़ता आम-जनजीवन है। महंगाई के लगातार बेलगाम बने रहने के बीच इसकी रफ्तार थामने के लिए आरबीआई ने कई बार रेपो दरों में भी बढ़ोतरी की है। अर्थव्यवस्था के आंकड़े चाहे जितने भी बेहतर स्थिति को दर्शा रहे हों, लेकिन आम लोगों का जीवन स्तर जिन जमीनी कारकों से प्रभावित होता है, उसी के आधार पर आकलन भी सामने आते हैं। पिछले करीब तीन सालों के दौरान कुछ अप्रत्याशित झटकों से उबरने के क्रम में अब अर्थव्यवस्था फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है, लेकिन इसके समानान्तर साधारण लोगों के सामने आज भी आमदनी और क्रयशक्ति के बरक्स जरूरत की वस्तुओं की कीमतें एक चुनौती की तरह बनी हुई हैं। हालांकि सब्जियों के दाम फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन दूध, मसालों के अलावा ईंधन की कीमतों के इजाफे ने फिर मुश्किल पैदा की है। यह स्थिति इसलिए भी खतरे की घंटी है कि आरबीआई इस समस्या के संदर्भ में फिर रेपो दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। यह अलग सवाल है कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई मौद्रिक नीतियां किस स्तर तक कामयाब हो पाएंगी? बदलते भारत को समझने में नाकाम विपक्ष, समझ ही नहीं पा रहा कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएं, उसने अक्सर आम जनता से जुड़े मुद्दों पर उदासीनता ही बरती है। 'नया भारत-सशक्त भारत' की बात करने वालों द्वारा हर वक्त कहा जा रहा है कि देश की आर्थिक विकास दर नियंत्रण में है। केंद्र सरकार की नजर में विकास की गति तेज है। राज्य सरकारें भी अपने-अपने राज्य में ऐसा ही दावा कर रही हैं। बोलते हैं उत्पादन बढ़ा है, संपत्ति बढ़ी है। कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, संचार, रक्षा, सैन्य साजोसामान, ज्ञान-विज्ञान सभी क्षेत्रों में तरक्की हुई है। राष्ट्र की प्रतिष्ठा और साख दुनिया में बढ़ी है। वे कहते हैं, सहरद से सरहद तक सड़कें बना रहे हैं, शहर बसा रहे हैं, भंडार अन्न से भरे हैं, बाजार माल से पटे हैं। खरीददार भी खूब है। अरबपतियों की कौन कहे, खरबपतियों की संख्या बढ़ रही है और दुनिया में नाम कमा रही है। भारत के डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीशियन, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, व्यापारी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। वे सभी ये सूचनाएं बिल्कुल सही-सही दे रहे हैं।

कांग्रेस में परिवार का वर्चस्व बना रहेगा

उमेश चतुर्वेदी

आम चुनावों के एक वर्ष पहले आयोजित अधिवेशन में कांग्रेस ने उन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है, जिसके जरिए कांग्रेस को बदलने की कोशिश हो रही है। अब तक पार्टी के संविधान के मुताबिक, पार्टी की सर्वोच्च नियामक इकाई कांग्रेस कार्यसमिति के लिए चुनाव होता था। लेकिन पार्टी इस बार उससे भी आगे बढ़ गई है। अब कांग्रेस कार्यसमिति में 50 प्रतिशत दलित, पिछड़ों को आरक्षण दे दिया गया है। बाकी बचे पचास फीसदी सीटों पर भी कांग्रेस युवाओं और महिलाओं को तवज्जो देने की तैयारी में है।

कांग्रेस के संविधान संशोधन के मुताबिक, अब कार्यसमिति में लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के नेताओं के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री भी स्थाई सदस्य होंगे। इसके लिए उन्हें अब अध्यक्ष की ओर से नामांकन की जरूरत नहीं रहेगी। दिलचस्प यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने पार्टी स्तर पर इससे भी आगे बढ़ गई है। पार्टी ने तय किया है कि एक जनवरी 2025 से पार्टी में सिर्फ डिजिटल सदस्यता ही होगी।

कांग्रेस के नए संविधान संशोधन के मुताबिक कांग्रेस की सदस्यता फॉर्म में थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर का भी कॉलम होगा। इसके साथ ही सदस्य की पत्नी और मां का भी नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। साफ है कि पार्टी थर्ड जेंडर और महिलाओं को यह संदेश देने की कोशिश में है कि उनके हितों का भी वह खयाल रखने जा रही है।

नए संविधान संशोधन के मुताबिक, अब प्रांतीय कांग्रेस समिति के आठ प्रतिनिधियों पर एक केंद्रीय सदस्य चुना जाएगा। इसके पहले तक छह प्रांतीय प्रतिनिधियों पर एक केंद्रीय सदस्य होता था। इसी तरह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों की संख्या को 1240 से बढ़ाकर 1653 कर दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों की संख्या को 24 से बढ़ाकर 35 किया गया है।

कांग्रेस के इस संविधान संशोधन पर चर्चा से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इस पर विचार आठ साल से चल रहा था। आठ साल पहले हुए आम चुनावों में जब कांग्रेस को करारी हार मिली थी, पार्टी ने उसी समय पार्टी के संविधान को बदलने की तैयारी शुरू कर दी थी। हार के बाद हुई कार्यसमिति की बैठक में तीन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जिसमें कांग्रेस में सक्रिय सदस्यों के विचार को फिर से स्वीकार किया गया था।

इसके साथ ही पार्टी के चुने हुए पदाधिकारियों के कार्यकाल को पांच साल से घटाकर तीन साल करने की बात हुई थी। उस बैठक में पार्टी की जिला एवं राज्य समितियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही अल्पसंख्यकों को पार्टी के पदों में पचास फीसद आरक्षण देने पर भी चर्चा हुई थी। हालांकि यह चर्चा ही रह गई और इसे लागू नहीं किया जा सका। तब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उस बैठक के पहले चर्चा थी कि बैठक में राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। हालांकि इस पर विचार नहीं हुआ।

कांग्रेस में संविधान समीक्षा का विचार पिछले साल 13 मई से 15 मई तक उदयपुर में हुई चिंतन बैठक में फिर से परवान चढ़ा। इसी चिंतन बैठक में सुझाव आया कि समयबद्ध संविधान समीक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए। यह भी तय हुआ कि कांग्रेस कार्यसमिति की मंजूरी से प्रांतीय समितियों को अपने अलग संविधान को भी मंजूरी दी जा सकती है। उस बैठक में यह भी सुझाव आया था कि पार्टी में एक परिवार एक टिकट पॉलिसी होनी चाहिए। यानी एक व्यक्ति के पास कांग्रेस में सिर्फ एक ही संगठनात्मक पद होना चाहिए।

उदयपुर की चिंतन बैठक के बाद अंबिका सोनी की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा समिति का गठन हुआ, जिसमें राहुल गांधी के नजदीकी रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल और जितेंद्र सिंह, जबकि सोनिया गांधी के नजदीकी मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश, अभिषेक मनु सिंघवी और दीपादास मुंशी शामिल किए गए। इस समिति के एक सदस्य जी परमेश्वरन भी हैं। गांधी-नेहरू परिवार के प्रति अंबिका सोनी की प्रतिबद्धता भी छिपी हुई नहीं है।

जाहिर है कि जिस समिति में सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के ही नजदीकी लोग शामिल होंगे, उनके समक्ष गांधी-नेहरू परिवार को ही समाहित करने का अदृश्य दबाव जरूर होगा। वैसे भी इस तथ्य को चाहे जितनी भी आलोचना की जाए, कांग्रेस के लिए गांधी-नेहरू परिवार अंतिम विकल्प है। कांग्रेस को छोड़कर पिछले कुछ दिनों में भले ही गुलाम नबी आजाद जैसे नेता बाहर जा चुके हों, लेकिन यह भारतीय राजनीति का कड़वा सच है कि कांग्रेस के लिए गांधी-नेहरू परिवार अपरिहार्य है। कांग्रेस के बुनियादी कार्यकर्ताओं तक को लगता है कि अगर गांधी-नेहरू परिवार की छाया पार्टी से हटी तो उसे बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के संविधान बदलने की जो कवायद हुई, वह बदलाव कम, गांधी-नेहरू परिवार का वर्चस्व बनाए रखने की कवायद ज्यादा लग रही है।

बदली हुई राजनीति परिस्थितियों में कांग्रेस पर भी दबाव है कि वह परिवारवाद से बाहर निकले। भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद को भारतीय राजनीति का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि सुविचारित लोकतांत्रिक सोच रखने वाला वोटर इसके विरोध में उठ खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोग इसे समझते नहीं है। लेकिन वे गांधी-नेहरू परिवार से दूर जा भी नहीं सकते। शायद यही वजह है कि कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों के मनोनयन का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया गया है। जाहिर है कि इसमें पर्दे के पीछे से गांधी-नेहरू परिवार की ही चलेगी। कांग्रेस लाख संदेश देने की कोशिश करे कि उसके असली बॉस मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गांधी-नेहरू परिवार ही पार्टी का असली बॉस है। हालांकि पार्टी ने उदयपुर चिंतन शिविर में एक परिवार एक टिकट का सिद्धांत स्वीकार करने पर जो विचार किया था, उसके भी मूल में परिवारवाद को लेकर उठ रही व्यापक आवाजें ही रहीं।

भाजपा इस मुद्दे पर आम चुनावों में एक बार फिर कांग्रेस को घेरकर पटखनी देने की कोशिश करेगी। इन अर्थों में देखें तो कांग्रेस का संविधान संशोधन और उसके जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कार्यसमिति में स्थापित करने की कोशिश पार्टी के लिए दोधारी तलवार हो सकती है। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो ऐन चुनावों के पहले पार्टी में बिखराव को रोकना पार्टी के लिए आसान नहीं था और अब उसने ऐसा कर दिया है तो वह भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मौका देगी। भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद विरोधी जो पिच मेहनत से तैयार की है, उस पर कांग्रेस को लाना और उस पर उसे शिकस्त देना भाजपा के लिए कहीं ज्यादा आसान होगा।

प्रसंग

विद्याधनं सर्वधनं प्रधानं

सन्त गाडगे महाराज का मुकाम बम्बई में था। एक दिन वे मन्दिर जा रहे थे कि उन्हें एक गरीब बूढ़ा दिखायी दिया, जो एक मकान मालिक से कह रहा था, जरा इस चिट्ठी को पढ़कर सुना दें, बड़ी मेहरबानी होगी। उस व्यक्ति ने चिट्ठी रख ली और उसे एक कुल्हाड़ी देकर कहा, पहले मेरी लकड़ियाँ फोड़ दे, फिर मैं उसके बदले चिट्ठी पढ़कर सुनाऊँगा। इस पर बूढ़ा बोला, मुझमें लकड़ियाँ फोड़ने की ताकत नहीं रही। आप मेरी चिट्ठी वापस कर दें। मैं इसे दूसरे से पढ़वाऊँगा। उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया और वह उस बूढ़े को गालियाँ देने लगा।

गाडगे महाराज वहाँ आये और उन्होंने कुल्हाड़ी लेकर सारी लकड़ियाँ फोड़ दीं और उन्होंने लकड़ियों को ठीक तरह से जमा भी दिया। फिर मकान मालिक से बोले, अब तो इसकी चिट्ठी वापस करोगे न! फिर उस चिट्ठी को लेकर एक राहगीर के पास गये और जब उसने मजमून पढ़कर सुनाया, तो वे बूढ़े से बोले, हम दोनों निरे गधे ही हैं। न तुझे पढ़ना-(लखना आता है, न मुझे और मजे की बात यह है कि हमारे पास पैसा भी नहीं है। हम लोग अगर चार अक्षर भी पढ़े होते, तो ऐसी गति काहे को होती ? सचमुच बिना शिक्षा का आदमी पत्थर होता है, पत्थर!

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

1971 भारत-पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई।
1999 अब्दुल रहमान अरब मूल के ऐसे प्रथम व्यक्ति बने जिन्हें इस्रायली सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया।
2000 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण द्वारा क्रोएशिया के जनरल तिहोमिर ब्लास्किच को 45 साल क़ैद की सज़ा।
2005 यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यूशचेंको की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय रक्षा परिषद ने इराक से अपने सैनिक वापस बुलाने का निर्णय लिया।
2006 फिलीपींस में आपातकाल हटा।
2007 पाकिस्तान ने हत्फ़-2 अब्दाली बेलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया।
2008 मेघालय में नई विधानसभा के लिए चुनाव में 75% मतदान हुआ। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के केन्द्र सरकार ने धन लक्ष्मी नामक नई योजना शुरू की। दक्षिणी अफ़ग़ानिस्तान में नाटो व अफ़ग़ान सुरक्षा बलों के अभियान में 22 आतंकी मारे गए।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

मण्डलब्राह्मणोपनिषद् (भाग-3)

गतांक से आगे...

सर्वप्रथम अनि मण्डल है। उसके ऊपर सूर्य मण्डल है। उसके बीच में सुधा स्वरूप चन्द्र मण्डल है। उसके बीच में अखण्ड ब्रह्म का तेजोमण्डल है। वह विद्युत् रेखावत् श्वेत और प्रकाशमान है। वही शाम्भवी मुद्रा का लक्षण है। उसका दर्शन करने से तीन स्वरूप दृष्टि में आते हैं। ये रूप अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा रूप हैं। निमोलित (पलक बन्द होने की स्थिति) दृष्टि अमावस्या स्वरूप है, अर्धनिमीलित दृष्टि प्रतिपदा स्वरूप है और पूरी तरह खुली हुई दृष्टि पूर्णिमा स्वरूप है। इसलिए पूर्णिमा रूप दृष्टि का ही अभ्यास करना चहिए।

उस (पूर्णिमारूप दृष्टि) का लक्ष्य नासिकाग्र है। जिस समय तालुमूल में प्रगाढ़ अन्धकार के दर्शन होते हैं, उस समय अभ्यास के द्वारा अखण्ड मण्डलाकार ज्योति दिखाई देती है। वही सच्चिदानन्द ब्रह्म है। इस प्रकार जब सहजानन्द में मन लीन हो जाता है, तब शाम्भवी मुद्रा (सिद्ध) होती है और उसे ही खेचरी मुद्रा कहते हैं। उसके अभ्यास से मन स्थिर हो जाता है, तत्पश्चात् बुद्धि स्थिर होती है। उसके चिह्न इस प्रकार हैं- सर्वप्रथम तारा के समान दिखाई देता है, तत्पश्चात् वज्र दर्पण (अर्थात् हीरे का दर्पण) जैसा दिखाई देता है, इसके पश्चात् पूर्ण चन्द्र मण्डल दिखाई देता है, इसके बाद नवरत्न प्रभा का मण्डल दृश्यमान होता है, इसके बाद मध्याह्न का सूर्य मण्डल परिलक्षित होता है, तत्पश्चात् क्रमशः अग्निशिखा मण्डल दिखाई देता है।

उस समय वह पश्चिमाभिमुख (आन्तरिक) प्रकाश दृष्टिगोचर होता है, जिसकी आभा धूम्र वर्णिक स्फटिकमणि तुल्य, बिन्दु (मनस्तत्त्व), नाद (बुद्धि तत्त्व), कला (महत्तत्त्व), नक्षत्र, खद्योत (जुगनू), दीप, नेत्र, सुवर्ण और नवरत्न आदि जैसी होती है। वही प्रणव का स्वरूप है।

प्राण और अपान वायु को एक करके कुम्भक धारण करे, तत्पश्चात् नासिकाग्र पर दृष्टि को एकाग्र करके दृढ़ भावना से करद्वय (दोनों हाथों) की अँगुलियों से षण्मुखी मुद्रा धारण करके प्रणव नाद का श्रवण करे, इसमें मन लीन हो जाता है।

ऐसा अभ्यास करने वाले को कर्म लिप्त नहीं करते। रवि के उदय और अस्त के समय (प्रातः सायं) कर्म (धर्मकृत्य) सम्पन्न किये जाते हैं, किन्तु चिदादित्य (चैतन्य स्वरूप आदित्य) का तो उदय-अस्त होता ही नहीं, इसलिए उसे जानने (अथवा दर्शन करने वाले के लिए कोई कर्म शेष नहीं रहते। शब्द और काल के लय हो जाने से मनुष्य दिवा और रात्रि से अतीत होकर सभी का परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसके द्वारा उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है और ब्रह्म के साथ एकत्व हो जाता है। उन्मनी अवस्था से व्यक्ति अमनस्क हो जाता है। निश्चिन्त अवस्था ही उसका ध्यान है। समस्त कर्मों का निराकरण (दूर करना) ही उसका आवाहन है। निश्चय ज्ञान ही उसका आसन है।

क्रमशः ...

विश्व श्रवण दिवस

3 मार्च को हर साल विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन एक खास प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। डब्ल्यूएचओ द्वारा हर साल लगाए जाने वाले इस कैंप में लोगों को बहरेपन की लगातार बढ़ रही समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनियाभर में लोगों को सुनने की क्षमता से संबंधित रोगों के प्रति बताया जाता है, ताकि बहरेपन के लगातार बढ़ रहे मामलों को कम किया जा सके।

लम्बे समय तक तेज संगीत और अन्य तरह के शोर के संपर्क में आने का खतरा कितना गंभीर है उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस शोर की वजह से दुनिया में करीब 12 से 35 वर्ष के 100 करोड़ लोगों पर स्थाई तौर पर बहरा होने का खतरा मंडरा रहा है। इससे न केवल उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है साथ ही शिक्षा और रोजगार की संभावनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 2050 तक करीब 250 करोड़ लोगों की कुछ हद तक सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। वहीं इनमें से करीब 70 करोड़ लोगों को श्रवण क्षमता में सुधार के लिए इलाज की जरुरत होगी। गौरतलब है कि सुनने की क्षमता में कमी का आना अथवा बहरापन ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपनी सुनने की क्षमता खो देता है।

इस बारे में डब्ल्यूएचओ के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डिपार्टमेंट की निदेशक बेंट मिकेलसन का कहना है कि निजी ऑडियो उपकरणों के असुरक्षित उपयोग और नाइटक्लब, बार, संगीत कार्यक्रम और खेल आयोजनों जैसे स्थलों पर तेज शोर के संपर्क में आने के कारण लाखों किशोरों और युवाओं की श्रवण क्षमता को नुकसान होने का खतरा है।

कैसे किया जा सकता है बचाव

हालांकि, कई बार सुनने से संबंधित समस्याएं कानों की संरचना में किसी प्रकार की गड़बड़ी या किसी अंदरूनी रोग के कारण होती है, जिनसे बचाव करना थोड़ा मुश्किल से नामुमकिन हो सकता है। हालांकि, फिर भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रख कर इसके खतरे को कम किया जा सकता है -

अधिक वॉल्यूम के साथ कोई संगीत न सुनें जैसे टीवी, रेडियो या म्यूजिक सिस्टम की आवाज। ईयरफोन का अधिक इस्तेमाल न करें और धीमी वॉल्यूम के साथ ही उन्हें सुनें। कानों में खुजली होने पर कॉटन पेन, पिन, उंगली या कोई नुकीली चीज न डालें। किसी अन्य व्यक्ति के ईयरफोन या इयरबड्स आदि का इस्तेमाल न करें। समय-समय पर हियरिंग टेस्ट कराते रहें ताकि किसी प्रकार की समस्या का पहले ही पता लगाया जा सके। कान में मैल न जमने दें और मुंह आदि धोते समय कानों को भी साफ करते रहें।

नेपाल में जारी है शह मात का खेल

रंजीत कुमार

अप्रैल 2008 में परंपरागत राजशाही को समाप्त कर नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना हुई। दुनिया भर में तब इसकी खूब प्रशंसा हुई और नेपाल के आम लोगों की खुशी कुछ ऐसी थी मानो उन्हें किसी विदेशी शासन से आजादी मिली हो। लेकिन मात्र 15 वर्ष की अवधि में नेपाल के राजनीतिक दलों ने दल-बदल, अवसरवाद, टकराव, खींचतान, सरकार बनाने और गिराने, पार्टियों के विलय, टूट आदि का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

15 वर्षों में नेपाल के लोग 13 प्रधानमंत्री, दो दर्जन से अधिक गठबंधन, अनगिनत अविश्वास प्रस्ताव आदि देख चुके हैं। इसलिए सीपीएन-एमसी के वर्तमान प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहल %प्रचंड% को दो महीने के भीतर दोबारा विश्वासमत प्राप्त करने की आवश्यकता हो गई है, तो यह अप्रत्याशित नहीं है।

नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीएन-यूएमएल ने पुष्प कमल दाहल %प्रचंड% की साझा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन-यूएमएल ने कहा है कि %राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, इसलिए वो समर्थन वापस ले रहे हैं।% यूएमएल के नेताओं का कहना है कि प्रचंड की पार्टी सीपीएन (एमसी) ने राष्ट्रपति चुनाव में यूएमएल के उम्मीदवार को समर्थन देने का वचन भंग कर दिया है। 10 जनवरी को हुए समझौते में यह वादा किया गया था कि प्रचंड की पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में यूएमएल के उम्मीदवार का समर्थन करेगी।

उल्लेखनीय है कि नेपाल में नौ मार्च को राष्ट्रपति का चुनाव होना है। भारत की तरह नेपाल में भी राष्ट्रपति का चुनाव जनप्रतिनिधियों के मतों से होता है। चुनाव में देश की सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पंडौल और दूसरी बड़ी पार्टी सीपीएन (यूएमएल) के सुभाषचंद्र नेमवांग आमने-सामने हैं।

नेपाल की शतरंजी राजनीति के लिए यह कोई नई बात नहीं है। वहां की लगभग सभी प्रमुख पार्टियां 15 वर्षों के भीतर कभी न कभी एक-दूसरे के साथ गठबंधन कर चुकी हैं और लगभग सभी गठबंधन असमय टूटे हैं। लेकिन सीपीएन (एमसी) और यूएमएल की हालिया टूट कई मामलों में पूर्व की टूट से भिन्न है।

गौरतलब है कि पिछले संसदीय चुनाव में सीपीएन (एमसी) ने नेपाली कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। लेकिन प्रतिनिधि सभा (संसद) की सीट के मामले में नेपाली कांग्रेस से बहुत पीछे रह गए प्रचंड सरकार बनाने के लिए यूएमएल से मिल गए। प्रचंड को हर हाल में प्रधानमंत्री बनने की जिद थी, लेकिन उनके पास मात्र 32 सीटें थीं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 89 सीटों वाली नेपाली कांग्रेस का दावा स्वभाविक था। प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस को आखिरी समय में धोखा देकर यूएमएल और आरपीपी के साथ साझा सरकार बना ली। अघोषित समझौता यह हुआ कि प्रतिनिधि सभा के आधे कार्यकाल यानी ढाई साल बाद सीपीएन (एमसी) यूएमएल के नेता केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे।

नेपाली राजनीति के विश्लेषकों का मानना है कि प्रचंड ने भले ही यूएमएल से समर्थन प्राप्त करने हेतु आधे-आधे समय के लिए प्रधानमंत्री पद की डील स्वीकार कर ली थी, लेकिन अंदर से उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। भारत की ही तरह नेपाल में भी कुछ मौकों पर राष्ट्रपति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार बनाने के लिए आमंत्रण देने और विश्वास मत हासिल करने का आदेश देने में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि वादे के बाद भी प्रचंड ने यूएमएल के नेता सुभाषचंद्र नेमवांग को राष्ट्रपति बनाने से इनकार कर दिया। सुभाषचंद्र नेमवांग और प्रचंड के बीच लम्बे समय से प्रतिद्वंद्विता रही है।

नेपाली संविधान के अनुसार राष्ट्रपति तीस दिन के भीतर प्रचंड को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल करने का आदेश दे सकते हैं। लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का कार्यकाल 13 मार्च को समाप्त होने वाला है और 9 मार्च को नए राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में प्रचंड पर तुरंत बहुमत साबित करने का दबाव नहीं है। बहुमत के लिए सीपीएन-(एमसी) को 138 सीट की आवश्यकता होगी। नेपाली कांग्रेस (89 सीट), माधव कुमार नेपाल की सीपीएन यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी (10 सीट) और इस फोल्डर की अन्य छोटी पार्टियों की मदद से वे इस आंकड़े को आराम से प्राप्त करते दिख रहे हैं।

लेकिन असल सियासी संकट इसके बाद शुरू होने की संभावना है। गौरतलब है कि नेपाली कांग्रेस और प्रचंड के बीच राजशाही के जमाने से ही प्रतिद्वंद्विता चलती आ रही है। नेपाली कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए कम्युनिस्ट एकता के नाम पर कई बार प्रचंड ने ऑल कम्युनिष्ट अलायंस तैयार किया। नेपाली कांग्रेस को रोकने के लिए ही चिर-प्रतिद्वंद्वी सीपीएन (एमसी) और यूएमएल ने 2020 में आपस में विलय कर लिया था। कहा जाता है कि इसमें नेपाल में मौजूद चीनी दूतावास ने भी बड़ी मेहनत की। यह अलग बात है कि विलय जल्द ही विखंडन में बदल गया और दोनों पार्टी वापस अपने पुराने स्वरूप में आ गई।

खबरों के अनुसार प्रचंड, नेपाली कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउबा और सीपीएन यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के नेता माधव कुमार के बीच गुप्त डील हुई है। इसके अनुसार, ये तीनों नेता बारी-बारी से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे और सदन में एक-दूसरे का समर्थन करेंगे। नेपाली राजनेताओं के पिछले रिकार्ड को देखते हुए इस डील के पूरे होने की संभावना बहुत कम है।

लेकिन सत्ताई अवसरवादिता के इतर अगर नेपाल के हालात पर गौर करें, तो स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। नेपाल की आर्थिक नीतियों में चीनी हस्तक्षेप और अन्य कारणों से नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने के कगार पर है। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। भारत की मदद से नेपाल की अर्थव्यवस्था कई बार कंगाल होने से बची है। चीन मदद और कर्ज की शर्तें को कठोर करता जा रहा है। लेकिन नेपाल के राजनेताओं को कुर्सी के खेल से ही फुर्सत नहीं है। आने वाले समय में नेपाल राजनीतिक उथल पुथल ही नहीं, अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था के कारण भी दुनिया की निगाह में रहेगा।

गांधी आज

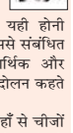

राजनीतिक स्वदेशी

हरएक देश की आर्थिक नीति यही होनी चाहिए कि जहाँ कच्चा माल हो वहीं उससे संबंधित उद्योग चलाने के कारखाने हों। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से इसीको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं।

कच्चे माल का विदेश जाना और वहाँ से चीजों की शक्ल में फिर स्वदेश लौटना आर्थिक दृष्टि से लाभजनक प्रतीत होता हो तो बहुत संभव है कि उसके मूल में स्वदेश में या विदेश में कोई अन्याय या अधर्म हो अथवा हिसाब लगाने में कहीं-न-कहीं भूल हो रही हो ।

इंगलैंड ने जिसे फ्री ट्रेड अथवा मुक्त द्वार व्यापार का नाम दे रखा है वह वास्तव में वैसा व्यापार नहीं है, क्योंकि वह अपने उद्योगों की रक्षा तथा दूसरे देशों के उद्योगों को मटियामेट करने के लिए जकात का नहीं बल्कि सैनिक-बल, राजनीतिक शक्ति और कुटिल नीति का उपयोग करता है। स्वदेशी की नीति का यह अधम और अन्यायी रूप है।

आर्थिक दृष्टि से स्वदेशी और बहिष्कार में भेद नहीं है। पर करोड़ों का जीवन अवलंबित हो वैसी वस्तु विदेशों से कदापि दी जा सकती। अर्थात् उसका बहिष्कार करना ही पड़ेगा। वह किसी खास देश के नहीं, बल्कि सब विदेशों के विरुद्ध होगा, इस स्वदेशी ही है। कौन कितना उपयोग व रहना चाहिए जैसे शर रहता है।

देश-विदेश के खिलाफ चलाया गया बहिष्कार राजनीतिक दृ किया जाता है, इसलिए उसका विचार इस प्रकरण में करने की आ नहीं।

संक्षिप्त समाचार

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने आज बच्चों को स्वर्ण प्राशन

रायपुर। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने 3 मार्च को रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में हर पुष्य नक्षत्र तिथि में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। चिकित्सालय के कौमारभृत्य बाल रोग विभाग में सवेरे नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक इसका सेवन कराया जाता है। यह औषधि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, श्वसन संबंधी एवं अन्य रोगों से रक्षा करने के साथ ही एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाने में अत्यंत लाभकारी है। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद करता है। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. लवकेश चंद्रवंशी ने बताया कि आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय का उद्देश्य केवल बच्चों की बीमारियों का इलाज करना ही नहीं है, बल्कि उनके स्वास्थ्य की गुणवत्ता को बढ़ाना और उन्हें बीमार होने से बचाना भी है। स्वर्ण प्राशन हर महीने की पुष्य नक्षत्र तिथि में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों को पिलाई जाने वाली औषधि है। डॉ. चंद्रवंशी ने बताया कि आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डॉ. जी.एस. बघेल, चिकित्सालय अधीक्षक प्रो. डॉ. प्रवीण कुमार जोशी और बाल रोग विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. नीरज अग्रवाल के निर्देशन में हर पुष्य नक्षत्र तिथि में महाविद्यालय चिकित्सालय में बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष की आगामी पुष्य नक्षत्र तिथियों 3 मार्च, 29 मार्च, 27 अप्रैल, 24 मई, 20 जून, 18 जुलाई, 14 अगस्त, 10 सितम्बर, 7 अक्टूबर, 4 नवम्बर, 1 दिसम्बर और 29 दिसम्बर को बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा।

दुर्ग से लेकर पटना के बीच एक होली स्पेशल ट्रेन

रायपुर। रेलवे बोर्ड ने होली को देखते हुए दुर्ग से लेकर पटना के बीच एक होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। जो दुर्ग से पटना और पटना से दुर्ग के बीच मात्र एक ही फेरा लगाएगी। जानकारी के मुताबिक रेलवे में त्यौहार के मौके पर काफी भीड़ चल रही है। सबसे अधिक भीड़ दुर्ग-बिलासपुर और गया-पटना के बीच चलने वाली ट्रेनों में हो रही है। इस भीड़ को ध्यान में रखते हुए एक होली स्पेशल सुपर फास्ट ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। यह ट्रेन दुर्ग-पटना-दुर्ग के मध्य एक फेरे के लिये चलाई जायेगी। दुर्ग से यह ट्रेन 08793 नंम्बर के साथ और पटना से 08794 नम्बर के साथ चलेगी। इस स्पेशल ट्रेन में 2 एसएलआर/एसएलआरडी, 4 सामान्य, 12 स्लीपर, 2 एसी-थ्री सहित कुल 20 कोच होंगे। दुर्ग से पटना के लिए चलने वाली होली स्पेशल 6 मार्च सोमवार को दोपहर 15 बजे छूटेगी और अगले दिन सुबह 9.30 बजे पहुंचेगी। इसी तरह पटना से 08794 पटना-दुर्ग 9 मार्च गुरुवार को 19.10 बजे छूटेगी और अगले दिन 10 मार्च को 21 बजे पहुंचेगी।

दीक्षा कल्याणक शोभायात्रा में शामिल हुए विकास उपाध्याय

रायपुर। श्री धर्मनाथ जिन प्रसाद एवं जिनकुशलसूरि दादावाडी अंजनशलाका प्रतिष्ठा एवं दीक्षा प्रसंगे दशान्हिका महोत्सव के मंगल कार्यक्रम के अवसर पर भव्यातिभव्य दीक्षाकल्याणक शोभायात्रा में संसदीय सचिव व विधायक विकास उपाध्याय शामिल हुए। यह कार्यक्रम श्री ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया गया था। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्र एवं देश के विभिन्न प्रदेशों से आए जैन समाज के लोग इस शोभायात्रा में शामिल हुए। विकास उपाध्याय ने कहा शोभा यात्रा निकालने का उद्देश्य श्री धर्मनाथ जिन प्रसाद एवं जिनकुशलसूरि के वाणी का उपदेशों का प्रचार प्रसार कर लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करना है। तीर्थंकर महावीर स्वामी अहिसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत था। हिंसा, पशुबलि, जात-पात का भेद-भाव जिस युग में बढ़ गया, उसी युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए जिसमें अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचैर्य (अस्तेय) और ब्रह्मचर्य हैं। इस अवसर पर श्री ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय कांकरिया, कार्यकारी अध्यक्ष अभय कुमार भंसाली, ट्रस्टी त्रिलोकचंद बरडिया, ट्रस्टी राजेन्द्र गोलछा, ट्रस्टी उज्जवल झाबक, रमेश झाबक सहित समाज के गणमान्य नागरिक और समाज के वरिष्ठजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होने आचार्य प्रवर श्री जिनमणीप्रभसूरीश्वरजी म.सा. एवं आचार्य प्रवर श्री जिनपीयुषसागरसूरीश्वरजी म.सा. से आर्शीवाद ग्रहण किया।

वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर ग्राम पंचायत खुटरापारा सचिव निलंबित

कोरिया। कार्य में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर सीईओ जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत खुटरापारा के सचिव दिलीप कुमार को निलंबित किया गया है। सीईओ जनपद पंचायत बैकुंठपुर के प्रतिवेदन अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में वित्तीय अनियमितता किये जाने संबंधित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। उक्त कृत्य हेतु सचिव ग्राम पंचायत खुटरापारा जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर को छ.ग. पंचायत सेवा नियम 1998 के नियम 3 एवं छ.ग. ग्राम पंचायत नियम, 1999 के नियम 4 एवं नियम 5 का उल्लंघन करने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त ग्राम पंचायत सचिव का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर में निर्धारित किया गया है।

सात चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की नीलामी पूरी

दो ने न्यायालय से लिया स्थगन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों में अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करने वाले लोगों को उनकी राशि वापस दिलाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। रायपुर जिले में चिटफंड कंपनी देवयानी प्रापर्टी लिमिटेड की संपत्तियों को नीलाम कर 9 हजार 866 निवेशकों को 4 करोड़ 14 लाख रूपये से अधिक की राशि वापस भी करा दी गई है। आज कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई बैठक में जिले में चिटफंड कंपनियों पर की जा रही कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक में चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की सही जानकारी प्राप्त कर उनकी नीलामी करने की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री बी.बी. पंचभाई सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिले में सात चिटफंड कंपनियों के संपत्तियों की ज्ञात संपत्तियों की नीलामी की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। इन कंपनियों के विरूद्ध थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इनमें से दो कंपनियों ने नीलामी के विरूद्ध न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है। देवयानी प्रापर्टी प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों की नीलामी कर 4 करोड़ 14 लाख 97 हजार 304 रूपये मिले है, जिन्हें जिले के 9 हजार 866 निवेशकों को लौटाया गया है। इसी प्रकार गोल्ड की इन्फ्रावेंचर लिमिटेड एवं बेसिड बेनीफोटो लिमिटेड की संपत्तियों की नीलामी से 81 लाख रूपये, निर्मल इन्फ्रा होम कार्पोरेशन लिमिटेड की संपत्ती की नीलामी से 51 लाख 51 हजार रूपये आरोग्य धन वर्षा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ती की नीलामी से 11 लाख 85 हजार रूपये और शुष्क इंडिया कंपनी लिमिटेड की संपत्ती नीलामी से 2 करोड़ 10 लाख 12 हजार रूपये शासकीय खातें में जमा हुए है।

बैठक में अधिकारियों ने यह भी बताया कि एचबीएन डेयरीज एण्ड एलाइड लिमिटेड की संपत्ती की भी नीलामी पूरी कर ली गई है। इस कंपनी की संपत्ती 10 करोड़ 30 लाख रूपये में नीलाम हुई है, परन्तु कंपनी ने एनसीएलटी से नीलामी के विरूद्ध स्थगन प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार किम इन्फ्रा डेवलपर्स लिमिटेड और नेक्टर कॉमर्शियल एस्टेट लिमिटेड कंपनी की संपत्ती भी 1 करोड़ 54 लाख 40 हजार रूपये में नीलाम की जा चुकी है। कंपनी ने इसके विरूद्ध बिलासपुर उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है। कलेक्टर डॉ. भुरे ने नीलामी से प्राप्त राशि को निवेशकों को लौटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को बैठक में दिए। उन्होंने न्यायालयों से स्थगन प्राप्त मामलों का बारिकी से अध्ययन कर दावा-आपत्ति समय-सीमा में न्यायालय में प्रस्तुत करने और प्रकरणों को तेजी से निराकृत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने जिले के निवेशकों के हित में अन्य जिलों से भी चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की नीलामी से मिली राशि प्राप्त करने के लिए पत्राचार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

ऑटो में निर्धारित संख्या से अधिक सवारी बैठाने पर होगी कार्रवाई

रायपुर। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने शहर की टैऊफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर गहन विचार -विमर्श किया। कलेक्टर ने शहर में चल रहे सवारी ऑटो में ओवर लोडिंग पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। शहर में ऑटो और छोटे सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर चालानी कार्रवाई करने के साथ-साथ चालक के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने के निर्देश भी कलेक्टर ने बैठक में दिए। उन्होंने व्यक्तिगत् परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कूटर-मोटरसाइकिलों और मोपेड जैसे दो-पहिया वाहनों को मॉडिफाइड कर मालवाहक के रूप में उपयोग को भी रोकने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने ऐसे मॉडिफाइड वाहनों को जप्त करने और उनके मालिकों तथा चालकों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुकान के बाहर पाटा लगाकर समान लगाने, ठेला खोमचा लगाकर यातायात बाधित करने वालों को हटाने के निर्देश दिए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल, सभी अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.डी.एम सहित यातायात प्रभारी और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर ने फाफाडीह चौक, अवंती बाई चौक पर स्थित बिजली के ट्रांसफारमरों को हटाने का काम तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने पचपेड़ी नाका, भाठागांव और संतोषी नगर ब्रिजो की सर्विस रोडों पर विद्युत खंबों को हटाकर अंडग्राउण्ड केबलिंग के काम की भी अद्यतन जानकारी अधिकारियों से ली। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस काम के लिए निविदा बुलाई गई है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जल्द ही इसके लिए कार्य एजेंसी तय कर दी जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने एक्सप्रेस वे फुण्डहर चौक से वी.आई.पी रोड के बीच भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने से दुर्घटनाओं की आशंका जताई। कलेक्टर ने कहा कि इस सड़क पर भारी वाहन चलने से सड़क भी जल्द ही खराब होगी। एक्सप्रेस वे फुण्डहर चौक से वी.आई.पी रोड के बीच भारी वाहनों को रोकने के लिए सड़क पर हाईगेज बेरियर लगाने पर बैठक में सहमति हुई। इसके साथ ही अवंती बाई चौक से क्रिस्टल आरकेड तक डिवाइडर बनाने की भी सहमति बैठक में हुई। कलेक्टर ने शहर में 9 और राष्ट्रीय राजमार्ग पर 15 नए चिन्हांकित किए गए ब्लैक स्पॉट को सुधारने के लिए रोड सेफ्टी इंजीनियरों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर सुधरात्मक उपाय सुझाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

लंबित कृषि पम्पों का कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण किये जाने का हैं प्रयास : मुख्यमंत्री

रायपुर। कृषि पम्प के अस्थाई व स्थाई कनेक्शन का मामला सदन में उठाए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि वित्तीय 2022-23 में कृषि पम्प ऊर्जीकरण हेतु 20,550 का लक्ष्य निर्धारित है और 9,490 कृषि पम्पों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है तथा 11,060 लंबित कृषि पम्पों का कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण किये जाने का प्रयास है।

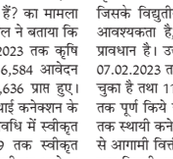

नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने प्रदेश में जनवरी, 2020 से दिनांक 07/02/2023 तक कृषि पम्प के अस्थाई व स्थाई कनेक्शन हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, कितने निरस्त हुए तथा स्वीकृत आवेदनों में कितनों में अस्थाई व स्थाई कनेक्शन दिए गए हैं व कितने लंबित हैं? का मामला सदन में उठाया। जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश में जनवरी 2020 से दिनांक 07/02 /2023 तक कृषि पम्प के स्थाई विद्युत कनेक्शन के कुल 1,16,584 आवेदन एवं अस्थाई विद्युत कनेक्शन के कुल 2,33,636 प्राप्त हुए। स्थाई कनेक्शन के 11,296 आवेदन तथा अस्थाई कनेक्शन के 16 आवेदन निरस्त किये गये हैं। प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत 95,393 आवेदन तथा दिनांक 31.12.2019 तक स्वीकृत लंबित 29,959 आवेदनों को मिलाकर कुल स्वीकृत आवेदन 1,25,352 में से 74,710 को स्थाई विद्युत कनेक्शन तथा अस्थाई विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त पात्र आवेदनों में से 2,33,620 को अस्थाई कनेक्शन प्रदाय किया गया। स्थाई कनेक्शन के स्वीकृत औपचारिकतापूर्ण 50,642 तथा अस्थाई कनेक्शन के निरंक आवेदन लंबित है।

कौशिक ने सवाल किया कि इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 31-01-2023 तक लंबित आवेदनों के निराकरण में कितनी राशि की आवश्यकता होगी व कितनी राशि बजट में उपलब्ध कराई गई, शेष राशि कब तक उपलब्ध कराई जावेगी? इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय 2022-23 में कृषि पम्प ऊर्जीकरण हेतु 20,550 का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विद्युतीकरण हेतु कुल राशि रूपए 205 करोड़ की आवश्यकता है, जिसके विरूद्ध बजट में 150 करोड़ का प्रावधान है। उक्त लक्षित 20,550 कृषि पम्पों में से दिनांक 07.02.2023 तक 9,490 कृषि पम्पों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है तथा 11,060 लंबित कृषि पम्पों का कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण किये जाने का प्रयास है। अतः दिनांक 07.02.2023 तक स्थाई कनेक्शन हेतु औपचारिकतापूर्ण लंबित आवेदनों में से आगामी वित्तीय वर्ष में 39,582 (50,642-11,060) कृषि पम्प विद्युतीकरण हेतु शेष रहेंगे, जिसके लिये आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग राशि रूपये 400 करोड़ की आवश्यकता होगी।

छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंशों पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी आज से

रायपुर। पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन कल 3 मार्च से प्रारंभ होगा। यह आयोजन 5 मार्च तक चलेगा। शोध-संगोष्ठी राजधानी रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय सभागार में आयोजित की जा रही है। पुरात्व एवं अभिलेखागार विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के क्षेत्रीय राजवंशों से संबंधित उपलब्ध स्रोतों के शोध अध्ययन द्वारा तत्कालीन इतिहास के विभिन्न पक्षों को प्रकाश में लाने और क्षेत्रीय इतिहास लेखन की समस्याओं पर विमर्श करने के उद्देश्य से तीन दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंशों से संबंधित विभिन्न पहलूओं, जैसे उनके वंशावलियों व कालक्रम पर नवीन प्रकाश, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास पर विमर्श किया जाएगा। संगोष्ठी में क्षेत्रीय

राजवंशों से संबंधित अभिलेख एवं सिक्के, कला एवं स्थापत्य का विकास, राजवंशों का अभ्युदय व पतन आदि विषयों पर वक्तागण और शोधार्थी शोधपत्रों का वाचन करेंगे। संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर प्रो. एल. एस. निगम छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश और इतिहास लेखन समस्याएँ' पर वक्तव्य देंगे। शोध संगोष्ठी में प्रो. व्योमपेश त्रिपाठी अमरकंटक, आचार्य रमेन्द्रनाथ मिश्र रायपुर, प्रो. चंद्रशेखर गुप्त नागपुर, प्रो. आर. एन. विश्वकर्मा राजनांदगांव, श्री जी.एल. रायकवार रायपुर श्री राहुल कुमार सिंह रायपुर, प्रो. दिनेश नंदिनी परिहार रायपुर और प्रो. के.के. अग्रवाल रायपुर राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय राजवंशों पर व्याख्यान देंगे। प्रथम दो दिन में 07 अकादमिक सत्र होंगे और प्रत्येक सत्र में 07 शोधपत्रों का वाचन और तदुपरांत वक्ताओं के व्याख्यान होंगे। अकादमिक सत्रों की समाप्ति उपरांत लोक सांस्कृतिक संस्थाओं माटी के सिंगार गिरहोला और लोकरंजनी लोककला मंच रायपुर द्वारा क्षेत्रीय राजवंशों क्रमशः सिरपुर के पाण्डुवंश और रतनपुर के कलचुरीवंश की गौरवगाथा पर केन्द्रित प्रस्तुतियाँ होगी।

विधानसभा में पुनीत राम और राधेश्याम को दी गई श्रद्धांजलि

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय पुनीत राम साहू और स्वर्गीय राधेश्याम शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के दोनों दिवंगत सदस्यों का जीवन परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय पुनीतराम साहू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सहज-सरल व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय साहू वर्ष 1985 से 1990 तक राजिम विधानसभा से विधायक चुने गए थे। वे अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे, वे 1970 में सहकारिता सोसायटी के अध्यक्ष बने, पंच-सरपंच रहे और फिगेश्वर जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी रहे। वे अंतिम समय तक सक्रिय रहे। उनका निधन प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय राधेश्याम शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहते हुए सामाजिक कार्यों में बड़ी भूमिका निभाई। वर्ष 1993 से वर्ष 1998 तक वे भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। किसान और सहकारिता नेता के रूप में उनकी पहचान रही।

अमन सिंह पर कसेगा शिकंजा

डीए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खास नौकरशाह और पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के भ्रष्टाचार की फाइल फिर खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें जनवरी 2022 में डीए मामले में पूर्व नौकरशाह अमन सिंह, उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अमन सिंह के पास अग्रिम जमानत मांगने के लिए तीन सप्ताह का समय है और उन्हें डीए मामले में जांच का हिस्सा बनने के लिए कहा है।

पिछले साल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व प्रधान सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मामला दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था और आरोप प्रथम दृष्टया थे।

दरअसल, रायपुर निवासी उचित शर्मा ने अमन सिंह और यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए एसीबी, ईओडब्ल्यू में शिकायत किया था। शिकायत के आधार पर एसीबी, ईओडब्ल्यू अपनी कार्रवाई शुरू की थी। इस कार्रवाई के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की थी। प्रारंभिक सुनवाई में ही हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ नो कोर्सिव स्टेप यानी किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

पुरखौती मुक्तांगन में नई साज सज्जा के साथ बढ़ायी जाएगी सुविधाएं

रायपुर। पुरखौती मुक्तांगन में नई साज-सज्जा कर इसे भव्य और आकर्षक बनाया जाएगा। संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत ने विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि पुरखौती मुक्तांगन में पर्यटक सुविधाएं बढ़ायी जाए। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले पर्यटक एवं सैलानियों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। संस्कृति मंत्री श्री भगत ने कहा कि पुरखौती मुक्तांगन में आने के लिए पर्यटकों को ऑनलॉइन टिकिट की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा टिकिट काउन्टर की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुरखौती मुक्तांगन में नई साज-सज्जा की जाए। यहां प्रवेश द्वारा को और आकिष भव्य और आकर्षक बनाया जाए। यहां पार्किंग-स्पेस को भी बढ़ाया जाए। चिन्हारी योजना की समीक्षा में उन्होंने अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा स्थानीय कलाकारों को मौका दिया जाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कलाकारों का पंजीयन, वरिष्ठता व राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए कार्यक्रमों के आधार पर उनका ग्रेडेशन करने और कलाकारों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कलाकारों के पंजीयन, चिकित्सा सुविधा, पेंशन संबंधी प्रकरणों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संस्कृति मंत्री श्री भगत ने बैठक में छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परम्परा के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए पर्यटन केन्द्रों तथा सूचना केन्दों में आदिम कला संस्कृति व राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की ब्रोशर, पोस्टर लगाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री भगत ने गढ़ कलेवा की प्रगति की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 33 जिलों में से 16 जिलों में गढ़ कलेवा का संचालन किया जा रहा है।

वैज्ञानिकों ने विद्यार्थियों के साथ साझा किए विज्ञान के व्यावहारिक अनुभव

रायपुर। छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेन्टर में 'वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान' थीम पर फोल्डस्कोप एजुकेशनल एवं अनुसंधान उपकरण' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। विज्ञान दिवस पर आयोजित इस तीन दिवसीय कार्यशालाओं में छात्रों और शिक्षकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से सस्ते एवं व्यवहारिक उपकरणों के उपयोग और रख-रखाव के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यशाला में फोल्डस्कोप के प्रयोग को हैण्ड-ऑन प्रशिक्षण द्वारा बहुत ही रोचक तरीके से समझाया गया। विभिन्न प्रकार के सैंपल प्लांट सेल, एनीमल सेल की स्लाइड, विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त किए गए जल के नमूने, बहुत से रसायनिक क्रियाओं प्राप्त होने वाले प्रोड्क्स, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ जैसे कई- एककोशीय एवं द्विकोशीय सूक्ष्म जीवों को फोल्डस्कोप से देखना सिखाया जो

कि अत्यंत रोमांचकारी था। वर्तमान समय में जहां माइक्रोस्कोप अत्याधिक महंगे, नाजुकता और उच्च रख-रखाव के कारण केवल प्रयोगशाला तक सीमित हो गये है। ऐसे में हमारे आस-पास के जीवन और सूक्ष्म जीवों को देखने के तरीके में बदलाव हेतु ओरिगेमी माइक्रोस्कोप - फोल्डस्कोप की जानकारी दी गई। फोल्डस्कोप ओरिगेमी प्रक्रिया से प्रेरित एक अल्ट्रा किफायती पेपर माइक्रोस्कोप है।

कार्यशाला में महानिदेशक डॉ. एस. कर्मकार ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर महान भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकटरमन को याद करते हुए उनके उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज रमन प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं में वैज्ञानिक सोच का विकास देश को नई दिशा प्रदान करता है। डॉ. कर्मकार ने विद्यार्थियों को मानव कल्याण के लिये शोध करने के लिए प्रेरित किया। परियोजना संचालक डॉ. शिरीष कुमार सिंह ने कहा कि राज्य के युवा वैज्ञानिक एवं विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी के उन क्षेत्रों का पहचान करना चाहिए, जिसमें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हों, जिस तरह राज्य सरकार द्वारा नरुवा, गुरुवा, घुरुवा और बाड़ी में विज्ञान एवं तकनीकी का समावेश कर मितव्ययी विज्ञान को नया स्वरूप प्रदान किया जा सकता है।

वैज्ञानिक अधिकारी श्रीमती प्रज्ञा कदम ने कहा कि वर्तमान समय में जहाँ भारत में संसाधनों की कमी है। ऐसे में इस तरह के सस्ते वैज्ञानिक उपकरण उन्हें विज्ञान में खोज करने हेतु वैज्ञानिक अभिरुचि जागृत करेंगे। अगर हर बच्चे के पास इस तरह का एक माइक्रोस्कोप आ जाए तो वह विज्ञान की पढ़ाई प्रयोगशाला तक सीमित न रहकर हमारे नियमित जीवनचर्या में शामिल हो जाएगा और विद्यार्थियों को निश्चय ही विज्ञान शिक्षण की ओर आकर्षित करेगा। कार्यक्रम में सम्मलित शासकीय स्कूल फुण्डहर एवं शासकीय स्कूल दलदल सिवनी के सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिये शुभकामना दिया।

संक्षिप्त खबरें

फैसला आने से पहले वाहन को राजसात नहीं कर सकते - हाईकोर्ट

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि आपराधिक मामले की सुनवाई पर फैसला आने से पहले वाहन को राजसात करने का आदेश सही नहीं है कवर्धा जिले के वाहन मालिक अनिल सेन की पिकअप वैन को सन 2017 में करीब 500 लीटर शराब के साथ जब्त किया गया था। बाद में जब्त वाहन को कलेक्टर ने राजसात करने का आदेश दे दिया। इसे छुड़ाने के लिए मालिक ने कमिश्नर कोर्ट में अपील की जहां उन्हें राहत नहीं मिली। इस पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई के बाद फैसला आया है। जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की बेंच ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के बिना ही किसी वाहन को राजसात करने का आदेश देना सही नहीं है। वाहन को राजसात करने संबंधी निर्णय आरोपी के दोषी साबित होने पर निर्भर करता है।

ईडी के समन पर सन्नी अग्रवाल पहुंचे दफ्तर, हुई पूछताछ

रायपुर। मनी लांड्रिंग और कोयले पर लेवी वसूली के मामले की पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए ईडी के समन पर भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल पुजारी पार्क स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी ने पिछले दिनों अग्रवाल के घर, और मंडल के प्रशासकीय विभाग श्रम संचालनालय में जांच की थी। इसके बाद आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। सन्नी सुबह 10.30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे। अपुष्ट खबरों के अनुसार बुधवार शाम 7 बजे भी कुछ और लोगों से भी पूछताछ की गई। पिछले दिनों घर पर हुए छापे के दौरान वे घर पर नहीं मिले थे।

विधानसभा में 4 हजार 144 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पारित

मुख्य बजट का आकार बढ़कर हुआ 1 लाख 15 हजार 385 करोड़ रूपए

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत 4 हजार 143 करोड़ 60 लाख, 71 हजार 652 रूपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। तृतीय अनुपूरक बजट में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई, आवास, भूजल संरक्षण, आजीविका, औद्योगिक प्रशिक्षण, कस्टम मिलिंग सहित विभिन्न मदों में अतिरिक्त राशि के प्रावधान रखे गए हैं। इस राशि को मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट का आकार 1 लाख 15 हजार 385 करोड़ रूपए हो गया है। तृतीय अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय हेतु 02 हजार 575 करोड़ रूपए और पूंजीगत व्यय हेतु 01 हजार 569 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट में 1 लाख 4 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था। प्रथम अनुपूरक में 2 हजार 904 करोड़ रूपए, द्वितीय अनुपूरक में 4 हजार 338 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया था। तृतीय अनुपूरक की राशि 4 हजार 144 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सदन में तृतीय अनुपूरक बजट में किए प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 24 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इन लक्ष्य की पूर्ति हेतु निर्माणाधीन कार्यों के लिये 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार कृषक जीवन ज्योति योजना में राज्य में 05 हॉर्सपॉवर तक के कृषि पंपों के लिये निशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मछली पालन हेतु भी कृषि के समान विद्युत दर की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मछली पालकों को भी कृषि पंपों के समान निःशुल्क विद्युत सुविधा का लाभ देने के लिये कृषक जीवन ज्योति योजना हेतु तृतीय अनुपूरक में 341 करोड़ की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धान मिलिंग का कार्य समय सीमा में पूरा करने हेतु कस्टम मिलिंग की दरों में वृद्धि की गई है। उक्त राशि राज्य सहकारी विपणन संघ को प्रतिपूर्ति करने हेतु 700 करोड़ रूपए, इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों के लिये 321 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिये 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिला चिकित्सालयों में दवाईयां तथा अन्य सामग्री की आपूर्ति के लिये 210 करोड़ रूपए और चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग के अधिग्रहण के लिए 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से महाविद्यालय के भवन एवं चिकित्सा उपकरणों की राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तृतीय अनुपूरक बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिये 116 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 42 लाख 10 हजार घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना के तहत विद्युत देयकों पर 01 हजार 115 करोड़ रूपये की राहत प्रदाय किया जाना है। इसके लिए 19 करोड़ 14 लाख का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक एवं स्वचालित उद्योगों की मांग को देखते हुए प्रदेश में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु टाटा टेक्नोलॉजी पुणे के साथ एम.ओ.यू. किया गया है।

इसके तहत 36 शासकीय आई.टी.आई. को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जायेगा। प्रत्येक आई.टी.आई. में नये उपकरण एवं तकनीक की स्थापना पर 33 करोड़ के मान से लगभग 12 सौ करोड़ रूपए की कार्य योजना तैयार की गई है।

विधानसभा में पुनीत राम साहू और राधेश्याम शर्मा को दी गई श्रद्धांजलि

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री पुनीत राम साहू और स्वर्गीय श्री राधेश्याम शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के दोनों दिवंगत सदस्यों का जीवन परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय श्री पुनीतराम साहू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सहज-सरल व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय श्री साहू वर्ष 1985 से 1990 तक राजिम विधानसभा से विधायक चुने गए थे। वे अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे, वे 1970 में सहकारिता सोसायटी के अध्यक्ष बने, पंच-सरपंच रहे और फिंगेश्वर जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी रहे। वे अंतिम समय तक सक्रिय रहे। उनका निधन प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्री राधेश्याम शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहते हुए सामाजिक कार्यों में बड़ी भूमिका निभाई। वर्ष 1993 से वर्ष 1998 तक वे भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। किसान और सहकारिता नेता के रूप में उनकी पहचान रही। मध्यप्रदेश विधानसभा में उन्होंने सभापति सहित कई समितियों में काम किया। नाबार्ड के चेयरमेन, मध्यप्रदेश किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष, रायपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष, इफको और कृभको के सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी यूनियन के चयनित प्रतिनिधि आदि अनेक पदों पर काम करने का गहरा अनुभव था। वे अपनी बात बेबाकी से रखते थे और आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाते थे। पूर्व विधायकों की समस्याओं की ओर भी उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया।

विपक्ष के अहम प्रस्ताव पर चर्चा से भागना जनता का अपमान- नारायण चंदेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने विधानसभा में नक्सली हिंसा में भाजपा कार्यकर्ताओं के मारे जाने के संबंध में चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सरकार के आचरण को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि सरकार चर्चा से भाग रही है।

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि जिस तरह की वारदात हो रही हैं, नक्सली वारदात में पिछले एक माह में हमारे 4 कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है, लगातार हमारे जवान भी मारे जा रहे हैं, धर्मांतरण दुर्भाग्यपूर्ण है, आम आदमी भय से ग्रस्त है। इस पर आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव रखा। हम लोगों ने बोलना शुरू किया लेकिन दुर्भाग्य

नेता प्रतिपक्ष बोले मंत्री नहीं चलने दे रहे सदन

है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव की चर्चा से इनकार कर दिया। चर्चा करने से भाग गई। विपक्ष के प्रस्ताव को अहमियत नहीं दी गई और परिस्थितियां विधानसभा में यह बनी कि छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री सदन को बाधित करते हैं। चर्चा नहीं होने देते। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। यह लोकतंत्र का सीधा अपमान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से खिलवाड़ है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सदन में चर्चा नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। चर्चा से रोका जाता है। सरकार चर्चा से पलायन करती है। यह सरकार चर्चा करने से कतराती है। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। हम चर्चा चाहते थे। हम आज भी चर्चा चाहते हैं।

हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सदन में चर्चा करना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार से जवाब चाहते हैं लेकिन कांग्रेस संसदीय मर्यादाओं का अपमान कर रही है और जनता के मुद्दों से भाग रही है।

विधानसभाः नक्सली हत्याओं पर सरकार ने नहीं की चर्चाः बृजमोहन

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दौरान स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने को लेकर वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में नक्सल घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं। हमारे चार भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है। नक्सली खून पर खून बहा रहे हैं और प्रदेश की कांग्रेस सरकार तमाशा बीन बनी हुई है।

बृजमोहन ने कहा कि कांग्रेस की सरकार निर्मम, संवेदनहीन सरकार है। लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। इनके 18 नेताओं को पहले नक्सलियों ने मारा बावजूद नक्सलवाद को लेकर ये गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 33 सालों से में विधायक हूं एक व्यक्ति की भी हत्या महत्वपूर्ण होती है अगर सदन में उस पर चर्चा की बात हो तो सरकार को आगे आकर स्वीकार करना चाहिए। परंतु यहां ऐसा नहीं है। प्रेम प्रकाश पांडे जब विधानसभा अध्यक्ष थे नक्सली घटना पर विधानसभा की गुप्त बैठकें होती थी।

अहंकार में डूबी सरकार सोचती है कि हम 14 भाजपा विधायकों को दबा देंगे तो यह उनकी गलतफहमी है। जनता की आवाज बनकर भाजपा के 14 विधायक सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार ने कसम खाई है गोली चलाने की तो हमने भी कसम खाई है सीना ताने रखने की।

सदन के भीतर भाजपा विधायकों ने पढ़ी हनुमान चालीसा

निलंबन पश्चात नाराज बृजमोहन अग्रवाल सहित भाजपा विधायकों ने सदन के भीतर हनुमान चालीसा का पाठ किया, धर्म की जय, जय श्रीराम के नारे लगाए और ओंकार का उद्घोष किया। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों को दरकिनार करती है इस कारण से हमने सरकार को सद्बुद्धि मिले और अपनी जिम्मेदारी समझे इस हेतु हनुमान चालीसा का पाठ किया।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष के संरक्षक होते हैं हम उनसे आग्रह करेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर ग्राहता पर चर्चा नहीं होगी तो प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत की भूमिका पर सवाल खड़े होंगे।

विपक्ष के अहम प्रस्ताव पर चर्चा से भागना जनता का अपमान- चंदेल

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने विधानसभा में नक्सली हिंसा में भाजपा कार्यकर्ताओं के मारे जाने के संबंध में चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सरकार के आचरण को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि सरकार चर्चा से भाग रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि जिस तरह की वारदात हो रही हैं, नक्सली वारदात में पिछले एक माह में हमारे 4 कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है, लगातार हमारे जवान भी मारे जा रहे हैं, धर्मांतरण दुर्भाग्यपूर्ण है, आम आदमी भय से ग्रस्त है। इस पर आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव रखा। हम लोगों ने बोलना शुरू किया लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव की चर्चा से इनकार कर दिया। चर्चा करने से भाग गई।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

भाजपा अपनी लड़ाई में कांग्रेस का नाम जबरिया घसीट रही

रायपुर। सूरजपुर के भैयाथान दो भाजपा नेताओं के आपसी झगड़े में कांग्रेस और सरकार को घसीटना तथा इस घटना के आधार पर गृमंत्री को पुतला जलाना भाजपा की ओछी मानसिकता है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सूरजपुर भैयाथान में रेत को लेकर हुये विवाद से स्पष्ट हो गया कि रेत के कारोबार और रेत तस्करी में भाजपा नेताओं की अहम भूमिका है। पूर्व रमन सरकार के दौरान रेत तस्करी से भाजपा नेताओं ने सिंडीकेट बना लिया था। रेत तस्करी में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह एवं उनके सहयोगी का संरक्षण था। 15 साल तक प्रदेश की नदियों को अवैध तरीके से रेत खनन कर दोहन किया गया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने पूर्व रमन सरकार में भाजपा नेताओं के द्वारा बनाये गये तस्करी के सिंडीकेट को तोड़कर तस्करों पर लगाम लगाया है। सूरजपुर में भाजपा नेता रेत के खेल में शामिल है एक-दूसरे के ऊपर हमला कर रहे है।

त्रिपुरा नागालैंड में भाजपा की जीत मोदी मॉडल का नतीजा

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने त्रिपुरा और नगालैंड में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत और मेघालय में भी अच्छे नतीजों पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल की जीत बताते हुए कहा है कि कांग्रेस तीनों राज्यों में बुरी तरह पिट गई। यह साबित हो गया है कि देश कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस अपने सफाए के लिए तैयार रहे। देश की जनता कांग्रेस के कर्मों और नीतियों की वजह से इस पार्टी से नफरत करने लगी है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों के चुनाव में हमारी जीत ने फिर जाहिर कर दिया कि देश की जनता की पसंद केवल भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। त्रिपुरा नागालैंड में भाजपा को समर्थन देकर जनता ने साफ संदेश दिया है कि उसे भ्रष्टाचार मुक्त विकास की राजनीति करने वाली भाजपा ही पसंद है। कांग्रेस को एक बार फिर नकार दिया गया है। तीनों राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कई नेता भी वहां कांग्रेस के तथाकथित भूपेश मॉडल की बात कर रहे थे। जनता ने पहले की तरह फिर से एक बार कांग्रेस का भ्रष्ट मॉडल ठुकरा दिया है। कांग्रेस की हार कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ एक और बड़ा कदम है। कांग्रेस के लिए जैसे निराशाजनक परिणाम त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में आये हैं वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी आने वाले हैं। जनता ने तय कर लिया है कि वह भ्रष्टाचार मुक्त और विकास की राजनीति करने वाली सरकार चाहती है।

कांग्रेस ने किसानों को छलने का काम किया है-संदीप शर्मा

रायपुर। भाजपा सांसद चुन्नीलाल साहू, रायपुर संभाग प्रभारी सौरभ सिंह, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं किसान नेता संदीप शर्मा के नेतृत्व में प्रभावित किसान आज भाजपा कार्यालय एकात्म

परिसर से प्रदेश के कृषि एवं सिंचाई मंत्री के निवास का घेराव करने के लिए निकले। इस दौरान सांसद चुन्नीलाल साहू ने कहा कि गरियाबंद एवं महासमुंद जिले के किसान सिकासेर बांध के पानी की मांग को लेकर पैदल यात्रा करते यहां तक आए हैं। कृषि एवं सिंचाई मंत्री रविंद्र चौबे से मिलकर महासमुंद व गरियाबंद जिले के सूखाग्रस्त खेतों एवं जलाशयों के लिए सिकासेर बांध का अतिरिक्त पानी जो व्यर्थ में बहा दिया जाता है, उसे नहर के माध्यम से सूखे खेतों एवं जलाशयों में लाने की मांग भाजपा द्वारा लगातार की जाती रही है। लेकिन प्रदेश के सिंचाई मंत्री और प्रदेश सरकार के नुमाइंदे इस विषय पर कोई कुछ नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सूखाग्रस्त खेतों को पानी दिलाने के लिए भाजपा ने पिछले 2 वर्षों से इस बात को सरकार के सामने रखा तब कहीं जाकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बजट में इसके लिए 1 करोड़ रुपए सर्वे के लिए जोड़ा लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि इस किसान विरोधी सरकार ने इसके लिए कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं दी।

नवीन कृषि अनुसंधानों एवं प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप शुरू करें कृषि छात्र - डॉ. चंदेल

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने विभिन्न कृषि संकायों

में अध्ययनरत विद्यार्थियों से आव्हान किया है कि वे कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में हो रहे नवीन अनुसंधानों तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी से संबंधित कौशल किसान अर्जित कर नये-नये नवाचार करें तथा उनपर आधारित अपना स्वयं का स्टार्टअप प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि कृषि तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित हो रहे नवीन अनुसंधानों तथा तकनीकों से इन क्षेत्रों में नवाचार तथा स्टार्टअप प्रारंभ करने हेतु बेहतर वातावरण तैयार हुआ है, जिसका विद्यार्थियों को लाभ उठाना के लिए आगे आना चाहिए। डॉ. चंदेल विश्वविद्यालय में संचालित कैरियर डेव्हलपमेंट सेन्टर द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (छ.ग.), भारतीय कृषि प्रबंधन अकादमी (छ.ग.), के सहयोग से "कृषि छात्रों में उद्यमशीलता हेतु कौशल विकास" विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का समापन कर रहे थे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कृषि छात्रों में कौशल विकास, नवाचार एवं उद्यमशीलता का विकास है।

होली के पहले मोदी ने महंगाई का बम फोड़ा - वंदना राजपूत

रायपुर। गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर 50 रुपये महंगा होने पर प्रदेश कांग्रेस

प्रवक्ता वंदना राजपूत ने केन्द्र सरकार के ऊपर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी धृतराष्ट्र बन गया है जिन्हें कमर तोड़ महंगाई दिखाई नहीं दे रहा है इसलिये भाजपा नेत्रियां भी आंख में पट्टी बांध लिये हैं और कान में रूई डाल लिये है ताकि बेलगाम महंगाई दिखाई एवं सुनाई ना दें। केंद्र में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से बेलगाम महंगाई ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। होली के पहले महंगाई का बम फूटा है 14.2 किलो के घरेलू रसोई सिलेंडर दाम में 50 रुपये और महंगा कर दिये है, अब एक रसोई गैस सिलेंडर को रिफीलिंग करवाने के लिये 1210 रुपये चुकाने पड़ेंगे। वहीं व्यावसायिक सिलेंडर भी लगातार महंगा होता जा रहा है। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में 800 रुपए महंगा हो गया है रसोई गैस सिलेंडर ये बहुत ही चिंता की विषय है। लेकिन भाजपा के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब यूपीए सरकार में गैस सिलेंडर के कीमत 410 रुपये होता था तब भाजपा के नेता कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार अबकी बार मोदी सरकार 12014 में मोदी ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था।

छत्तीसगढ़ मॉडल की हुई तारीफ

■ अपेक्स बैंक के अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं सहित ग्रामीण विकास के कार्यों की दी जानकारी

रायपुर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में छत्तीसगढ़ मॉडल एक बार फिर छाया रहा। विभिन्न राज्यों से सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों ने विकास के लिए 'छत्तीसगढ़ मॉडल' को अनुकरणीय बताया। छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चन्द्राकर ने छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही न्याय योजनाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी। राष्ट्रीय ग्राहक परामर्श समिति की बैठक में 15 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक में श्री बैजनाथ चन्द्राकर ने 'छत्तीसगढ़ मॉडल' का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की जनहितैषी नीतियों से गांव का विकास, किसानों का विकास, खेतिहर मजदूरों का विकास, आदिवासियों, महिलाओं का विकास सहित अन्य कृषि संबंधी गतिविधियों (अलाइड) का लगातार विकास हुआ है। किसानों को राहत देने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गो-धन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना एवं 65 प्रकार के वनोपजों का समर्थन मूल्य पर लेकर आयोग महत्ती भूमिका निभा रहा है। ऐसी कार्यशाला से महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ती है। आयोग द्वारा बीते

वर्षों में महिला सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए गए है। यह पहल महिला सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। कार्यशाला में बिलासपुर संभाग के सभी जिलों से 350 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दिया गया है। ये प्रतिभागी अपने-अपने क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करने का काम करेंगी। कार्यशाला में महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. श्रीमती नायक ने बताया कि महिला आयोग द्वारा विगत तीन वर्षों में 162 सुनवाई की जा चुकी है। आयोग की कार्यप्रणाली से महिलाओं का विश्वास आयोग पर बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोजित यह कार्यशाला एक अभियान है जो आगे भी निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए लड़कों और लड़कियों को समान अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं से तकनीकी के इस दौर में अपराधों के नए तौर-तरीकों को देखते हुए आवश्यक सतर्कता बरतने की बात कही। उन्होंने कहा कि आयोग की कोशिश है कि लोगों तक यथासंभव राहत पहुंचाएं। महिलाएं और बालिकाएं अपने उपर होने वाले किसी भी तरह के उत्पीड़न या शोषण को दबाएं नहीं बल्कि उनके खिलाफ बुलंद हौसलों के साथ आवाज उठाएं।

श्रीमती किरणमयी नायक ने कहा कि महिलाएं एवं बालिकाएं अपने उपर होने वाले उत्पीड़न एवं शोषण को बिल्कुल भी न सहें और इसके विरूद्ध आवाज उठाए। यदि किसी कारण महिला आयोग के कार्यालय नहीं आ पा रही है तो वाट्सअप पर मैसेज कर सकती है अथवा पत्र लिख सकती है। आयोग इसे संज्ञान में लेकर त्वरित करेगा। महिला आयोग के कॉल सेंटर 9098382225 पर यह मैसेज भेजा सकता है अथवा कॉल करके अपनी समस्या बताई जा सकती है।

महिलाओं को अपराध से बचने के बारे में दिया गया प्रशिक्षण- किरणमयी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा आज यहां स्व. लखीराम ऑडिटोरियम में महिलाओं के लिए संभाग स्तरीय विधिक जागरूकता प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मानव तस्करी, सायबर क्राइम और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के विभिन्न पहलूओं पर बारीकी से जानकारी दी गयी। कार्यशाला में महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक ने कहा कि महिलाओं को हमेशा अन्याय का विरोध करना चाहिए। इससे उनकी स्वतंत्रता और बढ़ेगी और वे निश्चिंत होकर कार्य कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपने आस-पास की महिलाओं को भी जागरूक करें। महिला सुरक्षा को